



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1984/वैशाख 8, 1906

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1984/VAISAKHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

सूचना

कां.प्रां. 1328.—केन्द्रीय सरकार, दरगाह खवाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इस्माइल एम. बावला को, जो एक हनफी मुस्लिम हैं 15 मई, 1984 से अजमेर दरगाह समिति का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. 11(1)/84-वक्फ]

जमाल अब्दुल समद, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 11th April, 1984

S.O. 1328.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby appoints, Shri Ismail M. Bawla, who is a Hanafi Muslim, as member of the Durgah Committee, Ajmer, with effect from the 15th May, 1984.

[No. 11(1)/84-Wakf]

JAMAL ABDUL SAMAD, Dy. Secy.

कां.प्रां. 1329.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनु-सरण में गभम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कस्तूरी लाल बन्सल, एडवोकेट, मंडी इबबानी, सरमा, हरियाणा ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे मंडी इबबानी जिला सरमा में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में भेजे जाना होगा।

[सं. 5 (23)/84-न्या.]

एस० गुप्ता, सहाय प्राधिकारी

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 11th April, 1984

NOTICE

S.O. 1329.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Kasturi Lal Bansal, Advocate,

Mandi Dabwali, Distt. Sirsa, Haryana for appointment as a Notary to practise in Mandi Dabwali.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(23)/84-JudL]

S. GOOPTU, Competent Authority

### गृह मंत्रालय

(कर्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1984

आदेश

का.आ. 1330.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 8 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 427, 435 और 436 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, षड्यंत्रों और षड्यंत्रों के तथा 30 अक्टूबर, 1983 को ओबरा ताप बिजली घर, ओबरा, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में हुई आग की घटना की बाबत बैसे ही संयोजन के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/25/83-ए.डी.डी.-II]

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 2nd April, 1984

### ORDER

S.O. 1330.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under Section 427, 435 and 436 of the Indian Penal Code, 1860 (Ait 45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction, in regard to incident of fire that took place on 30th October, 1983 at Obra Thermal Power Station, Obra Distt. Mirzapur (U.P.)

[No. 228/25/83-AVD.II]

आदेश

का.आ. 1351.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 427 और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 40 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, षड्यंत्रों और षड्यंत्रों के तथा 18 नवम्बर, 1983 को या उसके लगभग ओबरा ताप बिजली घर, ओबरा जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

बल गैसरी में केवल काटने की घटना की बाबत बैसे ही संयोजन के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/25/83-ए.डी.डी.-II]

एच. के. वर्मा, अवसर सचिव

### ORDER

1331.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under section 427 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) and section 40 of Indian Electricity Act, 1910, and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction, in regard to incident of cutting the cables in Cable Callary that took place on or about 28th November, 1983 at Obra Thermal Power Station, Obra, District Mirzapur (U.P.).

[No. 228/25/83-AVD.II]

H. K. VERMA, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

आय-कर

का. आ. 1332.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i)(ii) के अंतर्गत बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, कलकत्ता की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 जुलाई 1984 की अधिसूचना सं. 2574 के द्वारा दिए गए अनुमोदन की एतद्वारा 31 मार्च, 1984 तक सीमित किया गया है।

[सं. 5666/का.सं. 203/50/84 अ.क.नि. II]

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th February, 1984

### INCOME-TAX

S.O. 1332.—It is hereby notified for general information that the approval granted to Birla Institute of Scientific and Industrial Research, Calcutta vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 2574 dated 18-7-64 under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 is hereby restricted upto 31-3-1984.

[No. 5666/F. No. 203/50/84-IT'A. II]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

शुविध पत्र

(आय-कर)

का.आ. 1353.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10-8-1983 की अधिसूचना संख्या 5356 (का.सं. 203/136/83-आ.क.नि. II) में संस्था के नाम को "डा. जीवराज मेहता हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद" के स्थान पर "जीवराज मेहता स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद" पड़ा जाए।

[सं. 5680/का.सं. 203/136/83-आ.क.नि. II]

New Delhi, the 3rd March, 1984

## CORRIGENDUM

## INCOME-TAX

S.O. 1333.—It is hereby notified for general information that in Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 5356 (F. No. 203/136/83-ITA.II) dated 10-8-83, the name of the Institution be read as "Jivraj Mehta Smarak Trust, Ahmedabad" instead of "Dr. Jivraj Mehta Hospital and Research Institute, Ahmedabad".

[No. 5680/F. No. 203/136/83-ITA.II]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

आय-कर

का०आ० 1331.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 7-12-1977 की अधिसूचना सं० 2065 (फा० सं० 203/128/77-आ० का० नि०-II) के द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (ii) के अंतर्गत मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया गया अनुमोदन एतद्वारा 10-2-1984 से वापस लिया जाता है।

[सं० 5700(फा० सं० 203/57/84-आ० का० नि०-II)]

New Delhi, the 6th March, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 1334.—It is hereby notified for general information that the approval granted to Madras Institute of Technology, Madras under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 2065 (F. No. 203/128/77-ITA.II) dated 7-12-1977, is hereby withdrawn with effect from 10-2-1984.

[No. 5700/F. No. 203/57/84-ITA.II]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

आय-कर

का०आ० 1335.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 24-12-69 की अधिसूचना सं० 167 (फा० सं० 11/14/69-आ० का० नि०-II) की वैधता को, जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (ii) के अंतर्गत सूरि रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली को अनुमोदन दिया गया है एतद्वारा 31-10-1984 तक सीमित किया जाता है।

[सं० 5715/फा० सं० 203/64/84-आ० का० नि०-II)]

New Delhi, the 15th March, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 1335.—It is hereby notified for general information that the validity of Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 167 (F. No. 11/14/69-ITA.II) dated 24-12-69 granting approval under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to the Suri Research Foundation, New Delhi is hereby restricted upto 31-10-1984.

[No. 5715/F. No. 203/64/84-ITA.II]

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1984

(आय-कर)

का०आ० 1336.—इस कार्यालय की दिनांक 21-1-80 की अधिसूचना सं० 3145 (फा० सं० 203/8/80-आ० का० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित

किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि मसकयूलर डायस्ट्रोफी सोसाइटी, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय वसति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां वसति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

मसकयूलर डायस्ट्रोफी सोसाइटी, बम्बई।

यह अधिसूचना 31-12-1982 से 30-6-1984 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5718/फा० सं० 203/76/84-आ० का० नि०-II)]

New Delhi, the 16th March, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 1336.—In continuation of this Office Notification No. 3145-F. No. 203/8/80-ITA.II, dated 21-1-80, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Institution' subject to the following conditions:—

- (i) That the Muscular Dystrophy Society, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

## INSTITUTION

Muscular Dystrophy Society, Bombay.

This notification is effective for a period from 31-12-1982 to 30-6-1984.

[No. 5718/F. No. 203/76/84-ITA.II]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

(आयकर)

का० आ० 1337.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30-5-66 की अधिसूचना संख्या 56 (फा० सं० 10/37/66 आ० का० नि-II) द्वारा कोठारी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) के अधीन दिया गया अनुमोदन एतद्वारा 31-3-1984 तक सीमित किया जाता है।

[संख्या 5719/(फा० सं० 203/17/84 आ० का० नि-II)]

New Delhi, the 21st March, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 1337.—It is hereby notified for general information that the approval granted under section 35(1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 to Kothari Scientific & Research Institute, Calcutta vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 56 (F. No. 10/37/66-ITA.II) dated 30-5-66, is hereby restricted upto 31-3-1984.

[No. 5719 (F. No. 203/17/84-ITA.II)]

(आयकर)

का० आ० 1338.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगठन" प्रवर्ग के अर्थात् निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि मुख्य फाउण्डेशन फार एग्रीकल्चरल रिसर्च, कोयम्बतूर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजना के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देवदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संख्या

मुकुन्द फाउण्डेशन फार एग्रीकल्चरल रिसर्च, कोयम्बतूर

यह अधिसूचना 11-2-84 से 31-3-85 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5720(फा० सं० 203/115/82-आ० का० नि-II)]

## INCOME-TAX

S.O. 1338.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi. The prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

(i) That the Mukund Foundation for Agricultural Research, Coimbatore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research,

(ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said association will submit to the prescribed authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets-liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

## INSTITUTION

Mukund Foundation for Agricultural Research, Coimbatore.

This notification is effective for a period from 11-2-84 to 31-3-1985.

[No. 5720/F. No. 203/115/82-ITA.II]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1984

(आयकर)

का० आ० 1339.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अर्थात् निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि नेशनल सेवर लॉ एसोसियेशन नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजना के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देवदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संख्या

नेशनल सेवर लॉ एसोसियेशन, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 11-2-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5736(फा० सं० 203/243/82-आ० का० नि-II)]

New Delhi, the 31st March, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 1339.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read

with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the National Labour Law Association, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

#### INSTITUTION

National Labour Law Association, New Delhi.

This Notification is effective for a period from 11-2-1984 to 31-3-1985.

[No. 5736/F. No. 203/245/82-ITA.II]

(आय-कर)

का० आ० 1340.—इस कार्यालय की दिनांक 14-10-82 की अधिसूचना सं० 4950 (फा० सं० 203/75/82 आ० क० नि०-II) के मिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रायुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रयोगों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :

1. यह कि नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकारित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 14-9-1983 से 13-9-1986 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5735 (फा० सं० 203/70/84 आ० क० नि०-II)]

#### INCOME TAX

S.O. 1340.—In continuation of this Office Notification No. 4950 (F. No. 203/75/82-ITA.II) dated 14-10-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science

& Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

- (i) That the National Institute of Immunology, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

#### INSTITUTION

National Institute of Immunology, New Delhi.

This notification is effective for a period of three years from 14-9-1983 to 13-9-1986.

[No. 5735/F. No. 203/70/84-ITA.II]

आय-कर

का० आ० 1341.—इस कार्यालय की दिनांक 7-4-1982 की अधिसूचना सं० 4562 (फा० सं० 203/37/82 आ० क० नि०-II) के मिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रायुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम प्रयोगों" के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि आल इण्डिया इन्स्टिट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहबिलिटेशन सोसाइटी आयुर्विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकारित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

आल इण्डिया इन्स्टिट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहबिलिटेशन सोसाइटी फॉर प्रमोशन आफ मेडिकल रिसर्च, बम्बई।

यह अधिसूचना 20-12-83 से 19-12-86 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5734 (फा० सं० 203/15/84-आ० क० नि०-II)]

## INCOME TAX

S.O. 1341.—In continuation of the Office Notification No. 4562 (F. No. 203/37/82-ITA.II) dated 7-4-1982, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied science subject to the following conditions :—

- (i) That the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society for Promotion of Medical Research Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

## INSTITUTION

All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society for Promotion of Medical Research, Bombay.

This notification is effective for a period of three years from 20-12-83 to 19-12-1986.

[No. 5734/F. No. 203/15/84-ITA. II]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1984

शुद्धिपत्र

(आयकर)

का० प्रा० 1342.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22-10-1983 की अधिसूचना संख्या 5432 (का० सं० 203/138/82 प्रा० क० नि० II) की चौथी पंक्ति में आने वाले "खण्ड (ii)" शब्दों की "खण्ड (iii)" पढ़ा जाय।

[सं० 5747 (का० सं० 203/183/82-प्रा० क० नि० II)]

New Delhi, the 4th April, 1984

## CORRIGENDUM

## INCOME-TAX

S.O. 1342.—It is hereby notified for general information that in the Fourth line of Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 5432 (F. No. 203/183/82-ITA.II) dated 22-10-1983, the words "Clause (ii)" may be read as "Clause (iii)".

[No. 5747/F. No. 203/183/82-ITA.II]

(अय-कर)

का० प्रा० 1343.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम स्टडीज आन इम्प्यूनाईजेशन आफ कैंसर ग्रोथ कामन इन्सोसिटिड टिफ इन्फ्लामेस माक्रोप्लस

प्रायोजक का नाम

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०,  
बम्बई।

कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला

बिहार वेटेरिनरी कॉलेज, राजेन्द्र  
कृषि विश्वविद्यालय, पटना

शुरू करने की तारीख

1-1-1984

पूरा करने की तारीख

31-12-1986

अनुमानित परिधाय

1.44 लाख रुपये

बिहार वेटेरिनरी कॉलेज पटना, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (xiii) के अंतर्गत अनुमोदित है और प्रवर्तकता आधार पर परियोजना लेने के योग्य है।

[सं० 5745 (का० सं० 203/47/83-प्रा० क० नि० -II)]

## INCOME TAX

S.O. 1343.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi :—

Name of the scientific ,  
research project.

Studies on Immunisation of  
Cattle against Common  
Ixodid Tick, Boophilus Micro-  
plus.

Name of the sponsor.

M/s. Hindustan Lever Ltd.,  
Bombay.

Implementing Lab.

Bihar Veterinary College,  
Rajendra Agricultural  
University, Patna.

Date of commencement

1-1-1984.

Date of completion

31-12-1986

Estimated outlay

Rs. 1.44 lakhs.

2. Bihar Veterinary College, Patna stands approved under section 10(2)(xiii) of the I.T. Act, 1922 and is eligible to take project on sponsorship basis.

[No. 5745/F. No. 203/47/84-ITA.II]

आयकर

का० प्रा० 1344.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम डिबेल्फमेंट आफ टैक्नोलॉजी फार दि मैयूकेचर आफ जमरी आउट आफ स्वीट सोरगम।

प्रायोजक का नाम

मैसर्स किलोस्कर ब्रदर्स लिमि०,  
पुणे

कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला

निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च  
इन्स्टिट्यूट, फाल्टन

शुरू करने की तारीख

1-8-1982

पूरा करने की तारीख

31-7-1984

अनुमानित परिधाय

60,000 रुपये

निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फाल्तान ब्रिस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 जुलाई, 1982 की अधिसूचना सं० 4799 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अंतर्गत अनुमोदित है।

[सं० 5716 (फा० सं० 203/55/84-आ० क० नि०-I)]

### INCOME-TAX

S.O. 1344.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi :—

Name of the scientific	Development of Technology for the manufacture of Jaggery out of Sweet Sorghum.
Name of the sponsor	M/s. Kirlaskar Brothers Ltd., Pune.
Implementing Lab.	Nimbkar Agricultural Research Institute, Phaltan.
Date of commencement	1-8-1982.
Date of completion	31-7-1984.
Estimated outlay	Rs. 60,000/-.

2. Nimbkar Agricultural Research Institute, Phaltan stands approved under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 4799 dated the 13th July, 1982.

[No. 5746/F. No. 203/55/84-ITA.II]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

आयकर

का० आ० 1345.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है :-

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	बवालीफिकेशन आफ हार्डड्यूलिक बेरियेबल बाल्युम पम्प प्रेशर कन्ट्रोल वाल्व, फलो कंट्रोल वाल्व हार्डड्यूलिक ऐक्सेसरीज एंड पावर पैक फार अप्लिकेशन एण्डर सीस्मिक कंडीशन्स
प्रयोजक का नाम	मैसर्स बर्से स्पो आफ इंडिया लि० बम्बई
कार्यान्वित करने वाले का नाम	इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, मद्रास
शुरू करने की प्रस्तावित तारीख	सितम्बर, 1983
पूरा करने की प्रस्तावित तारीख	दिसम्बर, 1983
अनुमानित पन्थिय	50,500/-

2. इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, मद्रास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अंतर्गत अनुमोदित है और परियोजना को प्रायोजकता आधार पर लेने के योग्य है।

[सं० 5749 (फा० सं० 203/48/83-आ० क० नि०-II)]

मदन गोपाल चंद गोयल, अवर सचिव

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY

New Delhi, the 7th April, 1984

### INCOME-TAX

S.O. 1345.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi :

Title of the research Project	Qualification of Hydraulic Variable Volume Pump, Pressure Control, Valve, Flow Control Valve, Hydraulic Accessories and Power Packs for application under seismic conditions.
Name of sponsored	M/s. Vickers Sperry of India Ltd., Bombay.
Name of the implementing	Indian Institute of Technology, Madras.
Proposed date of Starting	Sept., 1983
Proposed date of completion	December, 1983
Estimated outlay	Rs. 50,500/-

2. Indian Institute of Technology, Madras is approved u/s. 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 and is eligible to take project on sponsorship basis.

[No. 5794/F. No. 203/48/84TA.II-I]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

(आय-कर)

का० आ० 1346.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इण्डियन काउन्सिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5692/फा० सं० 197/66/83-आ० क० (नि०-1)]

New Delhi, the 6th March, 1984

### (INCOME-TAX)

S.O. 1346.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Council for Child Welfare, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5692/F. No. 197/66/83-IT(AI)]

(आय-कर)

का० आ० 1347.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इण्डियन मिटिओरॉलॉजिकल सोसायटी, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5693/फा० सं० 197/121/81-आ० क० (नि०-1)]

## (INCOME-TAX)

S.O. 1347.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Meteorological Society, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5693 (F. No. 197/121/81-IT(AI))]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1984

(आयकर)

का० प्रा० 1348.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "भारत इण्डिया पिंगलवाडा सोसायटी (रजि०)" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5707/का० सं० 197/73/83-प्रा० क० (नि-1)]

[No. 5708/F. No. 197/197/83-IT(AI)]

## (INCOME-TAX)

S.O. 1348.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "All India Pingalwara Society (Regd.)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5707/F. No. 197/73/83-IT(AI)]

आयकर

का० प्रा० 1349.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "एम० के० टाटा ट्रस्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5708/का० सं० 197/197/83-प्रा० क० (नि-1)]

## (INCOME-TAX)

S.O. 1349.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "M. K. Tata Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5708/F. No. 197/197/83-IT(AI)]

(आयकर)

का० प्रा० 1350.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "गीता प्रतिष्ठान" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5709/का० सं० 197/32/82-प्रा० क० (नि-1)]

## (INCOME-TAX)

S.O. 1350.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gita Pratisthan" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5709/F. No. 197/32/82-IT(AI)]

(आयकर)

का० प्रा० 1351.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "स्किप्स फार प्रोग्रेस, बंगलोर" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5710/का० सं० 197/253/80-प्रा० क० (नि-1)]

## (INCOME-TAX)

S.O. 1351.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Skills for Progress, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83 to 1984-85.

[No. 5710/F. No. 197/253/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1984

(आयकर)

का० प्रा० 1352.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5724/का० सं० 197-क/196/82-प्रा० क० (नि-1)]

New Delhi, the 26th March, 1984

## (INCOME-TAX)

S.O. 1352.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Motilal Memorial Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 5724/F. No. 197-A/196/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1984

(आयकर)

का० प्रा० 1353.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "वि म्यूजिक ऐकेडेमी, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5737/का० सं० 197/239/83-प्रा० क० (नि-1)]

New Delhi, the 2nd April, 1984

## (INCOME-TAX)

S.O. 1353.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby



notifies "The Music Academy, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1985-86.

[No. 5737/F. No. 197/239/83-IT(AI)]

( आयकर )

का० आ० 1354—आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के उपखंड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "फादर मुल्लर चैरिटेबल इंस्टिट्यूट्स, मंगलूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5738/का० सं० 197/219/83-आ० क० ( नि०-1 )]

( INCOME-TAX )

S.O. 1354.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Father Muller's Charitable Institutions, Mangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1984-85.

[No. 5738/F. No. 197/219/83-IT(AI)]

( आयकर )

का० आ० 1355—आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "पद्मभूषण डॉ० एम० सी० मोदी पब्लिक ट्रस्ट, राजाजी-नगर, बंगलूर" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5739/का० सं० 197/115/82-आ० क० ( नि०-1 )]

( INCOME-TAX )

S.O. 1355.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Padmabhushan Dr. M. C. Modi Public Trust, Rajajinagar, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5739 F. No. 197/115/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

( आयकर )

का० आ० 1356—आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "वि थियोसोफिकल सोसाइटी, आदियार, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 और 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5757/का० सं० 197-क/195/82-आ० क० ( नि०-1 )]

आ० के० तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 1984

( INCOME-TAX )

S.O. 1356.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

notifies "The Theosophical Society, Adyar, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 and 1986-87.

[No. 5757/F. No. 197-A/195/82-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 1357—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नेशनल भार्गोविक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को केवल नौ लाख रुपये के उक्त समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए गए जाने वाले बारह करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के रूप में बन्धपत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर प्रभावी है।

[सं० 24/84-स्टाम्प-का० सं० 33/17/84-वि० क०]

New Delhi, the 12th April, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 1357.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the National Organic Chemical Industries Ltd., Bombay to pay consolidated stamp duty of Rupees nine lakhs only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of rupees twelve crores to be issued by the said Company.

[No. 24/84-Stamp-F. No. 33/17/84-ST]

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 1358—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त शुल्क को माफ करती है जो इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मात्र पांच करोड़ रुपये के बचन बन्धपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी है।

[सं० 25/84-स्टाम्प-का० सं० 33/18/83-वि० क०]

ORDER

STAMPS

S.O. 1358.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes of the value of rupees five crores only to be issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India are chargeable under the said Act.

[No. 25/84-Stamp-F. No. 33/18/83-ST]

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 1359—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विइला जुट और उद्योग लिमिटेड को बारह लाख मनामी हजार पांच सौ रुपये के उक्त समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए

जाने वाले छः करोड़ पचास लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों के रूप में बंध पत्रों पर प्रभावी है।

[सं० 27/84-स्टाम्प-फा० सं० 33/12/84-वि० क०]

भगवान दास, अवर सचिव

## ORDER

## STAMPS

S.O. 1359.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Birla Jute and Industries Limited to pay consolidated stamp duty of rupees four lakhs eighty seven thousand and five hundred, only chargeable on account of the stamp duty, on bonds in the form of debentures of the face value of rupees six crores and fifty lakhs to be issued by the said Company.

[No. 27/84-Stamp-F. No. 33/12/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

का० आ० 1360:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 के प्रावधान बाड़गेरा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि० को वर्ष 30 जून 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा और उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 18-2/84-ए० सी०]]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 11th April, 1984

S.O. 1360.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Badagara Co-operative Urban Bank Ltd. so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30th June, 1983 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 18—2/84-AC]

का० आ० 1361:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 के प्रावधान कोट्टारकरा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि०, कोट्टारकरा को वर्ष 30 जून, 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा और

उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 18-2/84 ए० सी०]

S.O. 1361.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966, shall not apply to the Kottarakara Co-operative Urban Bank Ltd., Kottarakara so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30 June, 1983 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 18-2/84-AC]

का० आ० 1362:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 के प्रावधान अनन्तसेनम् को-ऑपरेटिव बैंक लि०, त्रिवेन्द्रम को वर्ष 30 जून, 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ हानि-लेखा और उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० (18-2/84 ए० सी०)]

अमर सिंह, अवर सचिव

S.O. 1362.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Ananthasayanam Co-operative Bank Ltd., Trivandram, so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30-6-1983 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 18-2/84-AC]

AMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

का० आ० 1363:—राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 6 मार्च, 1984 से आरम्भ होने वाली तथा 5 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद्वारा श्री जे० ए० स० भटनागर को यूनियन बैंक आफ इण्डिया के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/13/84-ब० आ० I]

च० वा० भीरबन्धानी, निदेशक

New Delhi, the 7th April, 1984

S.O. 1363.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri J. S. Bhatnagar, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of the Union Bank of India for the period commencing on March 6, 1984 and ending with March 5, 1987.

[No. F. 9/13/84-BO.I]  
C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1984

क्र० आ० 1363.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दिए गए प्राप्ति के साथ संलग्न टिप्पणी (एफ०) के उपबन्ध में निम्नलिखित बैंकों पर, जहाँ तक कि 31 दिसम्बर, 1983 को उनके तुलनपत्रों का संबंध है, लागू नहीं होंगे:—

1. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
2. बैंक आफ बड़ोदा

[सं० 15/5/84-बी०आ० III]

New Delhi, the 9th April, 1984

S.O. 1364.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Note(f) appended to the form 'A' in the Third Schedule of the said Act shall not apply to the following banks viz:—

1. Central Bank of India,
  2. Bank of Baroda,
- in respect of their balance sheet as on the 31st December, 1983.

[No. 15/5/84-B.O.III]

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

क्र० आ० 1365.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) के उपबन्ध, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि उक्त उपबन्ध सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक की भारतीय नियामक ऋण और गारंटी निगम लि० के जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, निदेशक के रूप में नियुक्ति को प्रतिषेध करते हो।

[संख्या 15/19/83/बी०आ०-III]

New Delhi, the 11th April, 1984

S.O. 1365.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of sec-

tion 10 of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of the notification, to Central Bank of India and State Bank of India in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Managing Director respectively from being a director of the Export Credit and Guarantee Corporation of India Limited being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15/19/83-B.O.III]

क्र० आ० 1363.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक इसका संबंध यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता से इसकी शेयरों की धारिता से है।

[संख्या 15/6/84-बी०आ०-III]

S.O. 1366.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta, for a period of one year from the date of notification in respect of its holding of the shares in the United Industrial Bank Ltd., Calcutta.

[No. 15/6/84-B.O. III]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

क्र० आ० 1367.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 ख की उपधारा (1) के उपबन्ध 17 जून, 1984 तक बैंक आफ कोचीन, एर्नाकुलम लि० पर लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/7/84-बी०आ०-III]

माधव वैद्य, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 1984

S.O. 1367.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on recommendations of the Reserve Bank, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 10B of the said Act shall not apply to the Bank of Cochin Ltd., Ernakulam, till the 17th June, 1984.

[No. 15/7/84-B.O. III]

M. R. VAIDYA, Under Secy.

### वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1984

क्र० आ० 1368.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सैमसे मुविस्टेन्डेंट सर्विसिएल्स इन्स्पेक्टेड आफ इण्डिया, नई दिल्ली को इससे उपाबद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देता है।

## अनुसूची

1. मॅंगनीज डायक्साईड सहित कच्ची मॅंगनीज धातु,
2. कच्चा लोहा,
3. फ़ैरोमॅंगनीज के धातुमय सहित फ़ैरोमॅंगनीज,
4. निस्तप्त थोक्साईड सहित थोक्साईड,
5. मॅंगनीज डायक्साईड,
6. सांद्रित क्रोम सहित कच्चा क्रोम,
7. डकायनाईड,
8. सिल मेनाइट,
9. सांद्रित जिंक सहित कच्चा जिंक,
10. परिदग्ध और निस्तप्त मॅंगनेसाईड सहित मॅंगनेसाईड,
11. बैराइट,
12. लाल आक्साईड
13. पीला गैरिक,
14. सेलबेरी,
15. स्फीतीय।

[फा० सं० 5(7)/79-ई आई एण्ड ई पी]  
सी० बी० कुक्रेती, संयुक्त निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th April, 1984

S.O. 1368.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. Superintendence Surveillance Inspectorate of India, New Delhi, as an agency for the inspection of Minerals and Ores specified in Schedule annexed hereto prior to export.

## SCHEDULE

1. Manganese Ore, Excluding manganese dioxide.
2. Iron Ore.
3. Ferromanganese, including ferromanganese slag.
4. Bauxite, including calcined bauxite.
5. Manganese Dioxide.
6. Chrome Ore, including chrome concentrates.
7. Kyanite.
8. Sillimanite.
9. Zinc Ores, including zinc concentrates.
10. Magnesite including dead burnt and calcined magnesite.
11. Barytes.
12. Red Oxide.
13. Yellow Ochre.
14. Steatite.
15. Feldspar.

[F. No. 5(7)/79-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1984

फा० प्र० 1369:—केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 13), की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जून, 1984

को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिसकी उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[सं० 25012/31/81-रेगम]

ब्रम दत्त, संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)

(Department of Textiles)

New Delhi, the 18th April, 1984

S.O. 1369.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Silk Board (Amendment) Act, 1982 (13 of 1982), the Central Government hereby appoints the 1st June, 1984 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 25012/31/81-Silk]

BRAHM DUTT, Jt. Development Commissioner (Hand-Looms)

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)  
हैदराबाद, 21 दिसम्बर, 1983

विषय:—लाइसेंस संख्या पि/एस/1872461, दिनांक 14-9-82 का मुद्रा विनियम प्रति जो मैसर्स इंटिग्रेटेड डाटा सिस्टम्स प्रा. लि. हैदराबाद, के नाम जारी के रद्द करने का आवेदन।

फा० प्र० 1370:—ए.एम. 83 की नीति के अनुसार मिनि कम्यूटर/मैक्रो-प्रोसेसर के आयात करने के लिए मैसर्स इंटिग्रेटेड डाटा सिस्टम्स प्रा. लि. हैदराबाद के नाम परिशिष्ट 5 में सम्मिलित वस्तुओं के आयात के लिए आयात लाइसेंस सं० पि/एस/1872461, दिनांक 14-9-82, रु० 1,60,000 के लिए जारी किया गया था। मैस पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम की दूसरी प्रति जारी करने का इस कारण से अनुरोध किया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनियम प्रयोजन की मूल प्रति बम्बई हवाई परतब के कस्टम से रजिस्टर करने और आंशिक रूप में उपयोग के बाद गुम हो गया है। अब दूसरी प्रति जो जारी करना है उसका मूल्य रु० 39,750.10 होगा।

अपनी मांग के समर्थन में आवेदनकर्ताओं ने मोहरयुक्त कागज पर लेख्य प्रमाणक तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्थायी समिति द्वारा सत्यापित वापस पत्र वापर किया है।

मुझे सन्तुष्ट हुई है कि लाइसेंस सं० पि/एस/1872461, की मुद्रा विनियम की मूल प्रति बम्बई हवाई परतब के कस्टम से रजिस्टर करने तथा आंशिक रूप में उपयोग करने के बाद गुम हो गया है और आदेश देता हूँ कि मांगी गई मुद्रा विनियम की दूसरी प्रति आवेदनकर्ता को जारी की जाये। इसके फलस्वरूप लाइसेंस की मुद्रा विनियम की मूल प्रति सं० पि/एस/1872461 दिनांक 14-9-82, रद्द की जाती है।

[फाइल सं० आईटी.सी/एयू/एम/एस आई/67/एम83/हैदराबाद]

प्रार. लेखक राज उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)  
Hyderabad, the 21st December, 1983

Subject:—Order of Cancellation of Exchange Control Copy of Licence No. P/S/1872461 dt. 14-9-82 issued in favour of M/s. Integrated Data Systems Pvt. Ltd., Hyderabad. 4.

S.O. 1370.—M/s. Integrated Data Systems Pvt. Ltd., 6-3-542/3, Panjagutta, Hyderabad-4 were granted an import licence No. P/S/1872461 dt. 14-9-82 for import of items covered by Appex. 5 for Rs. 1,60,000 as per AM 83 period Policy for the end product Mini-Computer/Micro Processor. They have now applied for duplicate Exchange Control Copy

of the above licence on the ground that the original exchange control copy of the above licence has been lost after having been registered with Bombay Air Port Customs and utilised Partly. The total amount for which the duplicate required now is to cover the balance value of Rs. 39,75.10.

In support of this contention, the applicants have filed an affidavit on stamped paper duly attested by the Notary and Additional Standing Council, Central Government, Hyderabad.

I am satisfied that the original Exchange Control copy of the licence No. P/S/1872461 dt. 14-9-82 has been lost after having been registered with Bombay Air Port Customs and utilised partly and direct that duplicate exchange control copy of the licence in question should be issued to the applicant. The original exchange control copy of the licence No. P/S/1872461 dated 14-9-82 is cancelled.

[File No. ITC/AU/SSI/67/AM. 93|HYD]]

R. SELVARAJ, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

अहमदाबाद 27 जनवरी 1984

### अधिसूचना

विषय:- सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि० बड़ौदा को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० पी/सी/1958773/सी/एक्सचेंज/86/ए/82 दिनांक 11.3.1983 को रद्द करना

का० आ० 1371-सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि०, बड़ौदा को निम्नलिखित के आयात के लिए 5,70,609 रु. (पांच लाख सत्तर हजार छः सौ बी स. मात्र) का लाइसेंस सं० पी/सी/1958773 दिनांक 11.3.1983 प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य
1.	200 एम एल क्षमता के जंगाबरोखी इस्पात के सैपलिंग मिलेंडर/डबल कनेक्टर टाइप वॉ फाइन कंट्रोल नीडल वाल्वस ऑपरेटिंग प्रेशर 1800 पी.एस.आई.जी. के साथ सम्पूर्ण। प्रत्येक मिलेंडर जिसमें अस्टिंग डिस्क होल्डर डिस्क 1600 पी.एस.आई.जी./एक वाल्व सचरेडर क्लिक फिट और रिलीज मेल कपलिंग सहित है।	20 नग	12211.40
2.	जंगाबरोखी इस्पात सैपलिंग मिलेंडर 500 एम एल क्षमता के, डबल कनेक्टर टाइप वॉ फाइन कंट्रोल नीडल वाल्वस ऑपरेटिंग प्रेशर 180 पी.एस.आई.जी. सहित प्रत्येक मिलेंडर अस्टिंग डिस्क होल्डर सहित और डिस्क 1600 पी.एस.आई.जी. वॉ वॉ वाल्व सचरेडर क्लिक फिट और रिलीज मेल कपलिंग सहित	15 नग	11505.30
3.	चाजिंग लीड्स प्रत्येक 36" लंबे सहित स्टैंडर्ड सचरेडर मेल कपलिंग और फीमेल चैक यूनिट सहित।	15 नग	12006.00
			35722.70
	सीमा तक भाड़ा और बीमा		588.00
	कुल लागत बीमा भाड़ा		36310.70

(कुल तीन (3) मदें मात्र)

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुमति प्रतियां जारी करने के लिए हम आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रतियां और मुद्रा-वित्तिय नियंत्रण प्रतियां किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करण बिना और विलुप्त भी उपयोग में लागू बिना ही खो गई है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदकों ने न्यायिक जिलाधीश, बड़ौदा के सम्मुख विधिवत् गणप लेकर एक गणप-पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी/सी/1958773 दिनांक 11-3-1983 की सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा वित्तिय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं और निवेश देता हूँ कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुमति प्रतियां जारी की जाए।

उक्त लाइसेंस की मूल प्रतियां पत्रद्वारा रद्द की जाती हैं।

[मि० सं० 188/ईयू०/अप्रैल-मार्च 83/18062/सीजीसैल]

बी० रामाराव, डी० मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

Ahmedabad, the 27th January, 1984

NOTIFICATION No. 6

Subject.—Cancellation of Import Licence No. P/C/1958773/C/XX/86/A/82 dt. 11-3-1983 issued to M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Baroda.

S.O. 1371.—M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Baroda has been granted Licence No. P/S/1958773 dt. 11-3-1983 for Rs. 570609 (Rupees five lakhs seventy thousand six hundred nine only) for Import of following.

Sl. No.	Description	Qty.	Value
1.	Stainless steel sampling cylinders 200 ML capacity. Double connector type complete with two fine control needle valves operating pressure 1800 P.S.I. G. max. each cylinder fitted with bursting disc holder with disc/1600 P.S.I. G./one valve fitted with schrader quick fit and release male coupling	20 Nos.	12211.40
2.	Stainless steel sampling cylinders 500 ML capacity double connector type complete with two fine control needle valves operating pressure 1800 P.S.I. G. max. each cylinder fitted with bursting disc holder with disc/1600 P.S.I. G./one valve fitted with schrader quick fit and release male coupling	15 Nos.	11505.30
3.	Charging leads 36" long each with standard schrader male couplings and female check unit.	15 Nos.	12006.00
	Freight and insurance to the extent of		588.00
	Total GIF		36310.70

(TOTAL THREE (3) ITEMS ONLY)

They have applied for issue of duplicate copies of the above licence on the ground that the original Customs copy and Exchange Control copies have been lost without having been registered with any Customs Authority and utilised at all.

In support of their claim the applicants have filed an affidavit duly sworn before the Judicial Magistrate, Baroda.

I am satisfied that the Customs Purpose and Exchange Control copies of the licence No. P/C/1958773 dt. 11-3-1983 have been lost and direct that the duplicate copies of the said licence be issued to the applicant.

The original copies of the said licence are hereby cancelled.

[F. No. 188/EU/AM 83/18062/CG Cell]

V. RAMARAO, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

## ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

का० आ० 1372.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए। पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनडोपाबल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए

राज्य :—गुजरात	जिला :—महस	तालुका :—अंकलेश्वर			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर ए. आर.	सेन्टियर	है	
तेलावा	134	0	00	84	
	135	0	05	00	

[सं० O-12016/10/84-प्रोड०]

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 7th April, 1984

S.O. 1372.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provide that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Right of user for wire bed and anode bed

State: Gujarat	District: Bharuch	Taluka: Ankleshwar			
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-	are
Telwa	134	0	00	84	
	135	0	05	00	

[No. O-20116/10/84-Prod.]

का० आ० 1373.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वा० जे० डी० ए० से थी जी० एम० विराज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनडोपाबल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत :—

## अनुसूची

कूप नं० वी० जे० डी० ए० सी जी० जे० एम० विराज तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात	जिला :—मेहसाणा	तालुका :—कडई			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर ए. आर.	सेन्टियर	है	
नाना कडई	203/2	0	02	95	
	203/1	0	11	16	
	203	0	03	85	
	180	0	28	11	
	181	0	11	02	

[सं० O-12016/9/84-प्रोड०]

S.O. 1373.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from VIDA to VIRAJ in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from Well No. VJDA to GGS Viraj

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : KADI		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nani Kadi	203/2	0	02	95
	203/1	0	11	16
	203	0	08	85
	180	0	28	14
	181	0	11	02

[No. O-12016/9/84-Prod.]

का० आ० 1374.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला व तालुका :—मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए आर सेन्टीयर	ई
जुटाना	1249	0	02	06
	1251	0	01	70
	1252	0	04	88

[सं० O-12016/12/84-प्रोड०]

S.O. 1374.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3, of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Right of user for wire bed and anode bed.

State : Gujarat	District & Taluka : Mehsana		
Village	Block No.	Hectare	Are Centiare
Jotana	1249	0	02 06
	1251	0	01 70
	1252	0	04 88

[No. O-12016/12/84-Prod.]

का० आ० 1375.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य से हजीरा में उद्घाटन के लिये पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

हजीरा से उद्वन तक गैस नाला बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—सुरत तालुका :—चोपासी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर सेन्टीयर	ई
इच्छापुर	779	0	27	15

[सं० O-12016/16/84-प्रोड०]

S.O. 1375.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira to Utran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### Pipeline from Hajira to Utran

State : Gujarat	District : Surat	Taluka : Choriyasi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ichhapore	779	0	27	15

[No. O-12016/16/84-Prod]

का० अ० 1375.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम०एन०जी०सी० से एम०एन०एक्स तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाव्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणख एतद्द्वारा घोषित किया है;

अर्थात् कि उक्त भूमि में श्रितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की सहायता।

### अनुसूची

एम०एन०जी०सी० से एम०एन०एक्स तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला व तालुका	मेहसाना		
गांव	ब्लॉक न०	हेक्टेयर	एकर	सेंटियर
1	2	3		
कसलपुरा	334	0	09	24
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	773	0	06	84

1	2	3	4	5
कसलपुरा—जारी	773	0	06	36
	774	0	01	32
	776	0	08	40
कार्ट ट्रैक		0	03	60
942		0	01	68
941		0	04	56
कार्ट ट्रैक		0	05	88
825		0	12	00

[सं० O-12016/20/84-प्रोड०]

S.O. 1376.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNBC to SNX in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said Land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### Pipeline from D.S. No. SNBC to SNX

State : Gujarat	District & Taluka : Mehsana			
Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpura	334	0	09	24
	Cart track	0	00	6
	773	0	06	84
	772	0	06	36
	774	0	01	32
	776	0	08	40
	Cart track	0	03	60
	942	0	01	68
	941	0	04	56
	Cart track	0	05	88
	825	0	12	00

[No. O-12016/20/84-Prod.]

का० अ० 1377.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायरलेस बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाव्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार



ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनियमित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

वायर बेड और वेड बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—सूरत	तालुका:	चोयासी
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर एम्प्राई	सेंटीयर
ओखा	84	0	04 75

[सं० O-12016/11/84-प्रोड०]

S.O. 1377.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Right of User for wire bed and anode bed.

State : Gujarat	District : Surat	Taluka : Choryasi
Village	Block No.	Hectare Acre Centiare
Okha	84	0 04 75

[No. O-12016/11/84-Prod.]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1984

कां० प्रा० 1378.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 4147 तारीख 21-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

69 GI/84—3

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : ओलपाड		
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एम्प्राई	सेंटीयर
पाखड़ी	159	0	00	95
	160	0	24	60
	179	0	25	80
	178	0	21	10
	182	0	23	70
	183	0	07	08
	184	5	05	30
	185	0	13	60
	209	0	15	80
	210	0	01	40
	211	0	27	00
	212	0	00	35
	214	0	26	40
	215	0	32	50
	216	0	40	20
	218	0	12	50
	30	0	27	50
	31	0	01	90
	19	0	41	10
	17	0	38	35
	18	0	01	50
	38	0	21	90
	40	0	06	75
	49	0	24	45
	50	0	28	20
	345	0	71	50
	काट्टे ट्रेक	0	12	80
	344	0	30	50
	343/ए	0	33	00
	74	0	51	60
	75	0	19	05

[सं० O-12016/26/83-प्रोड०]

New Delhi, the 9th April, 1984

S.O. 1378 —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4147 dated 24-10-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further where the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat	District : Surat	Taluka : Olpad			
Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare	
Bharudi	159	0	00	95	
	160	0	24	60	
	179	0	25	80	
	178	0	21	10	
	182	0	23	70	
	183	0	07	08	
	184	0	05	30	
	185	0	13	60	
	209	0	15	80	
	210	0	01	40	
	211	0	27	00	
	212	0	00	35	
	214	0	26	40	
	215	0	32	50	
	216	0	40	20	
	218	0	12	50	
	30	0	27	50	
	31	0	01	90	
	19	0	41	10	
	17	0	36	35	
	18	0	01	50	
	38	0	21	90	
	40	0	06	75	
	49	0	24	45	
	50	0	28	20	
	345	0	71	50	
	Cart track	0	12	80	
	344	0	30	50	
	343/A	0	33	00	
	74	0	51	60	
	75	0	19	95	

[No. O-12016/26/83-Prod.]

कां० प्रा० 1379.—यतः पेट्रोलियम और अजित पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 4155 तारीख 25-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार को निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हजिरा बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका : चोरीया			
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एकर	सेंटीयर	
विहल	2	0	30	00	
	34	0	53	25	
	32	0	39	00	
	31	0	01	40	
	33	0	15	75	

[सं० O-12016/29/83-प्रोड.]

S.O. 1379.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4155 dated 25-10-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further where the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat	District : Surat	Taluka : Choriya			
Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare	
Vihal	2	0	30	00	
	34	0	53	25	
	32	0	39	00	
	31	0	01	04	
	33	0	15	75	

[No. O-12016/29/83-Prod.]

कां.ग्रां. 1380.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां. ग्रां. सं. 4449 तारीख 9-11-1983 द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अर्पण आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची उपयोग विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

यतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका : ओलपाड		
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ग.आर.ई.	सेंटीयर
कोसम	104	0	18	21
	99	0	2	02
	101	0	03	04
	100	0	65	76
	90	0	08	09
	89	0	01	01
	88	0	36	42
	92	0	05	06
	93	0	06	07
	94	0	05	06
	70	0	36	42
	59	0	19	22
	60	0	02	02
	8	0	43	50
	7	0	05	06
	6	0	17	20
	5	0	14	16
	402	0	37	43
	398	0	10	12
	10	0	33	39
	393	0	23	27
	394	0	59	69
	390	0	36	42
	386	0	03	04
	387	0	30	35
	384	0	11	13
	388	0	10	12
	95	0	00	15

[सं. O-12016/142/83-प्रोड.]

S.O. 1380.—Whereas by notification of the Government to India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4449 dated 9-11-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further where the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
Kosam	104	0	18	21
	99	0	02	02
	101	0	03	04
	100	0	65	76
	90	0	08	09
	89	0	01	01
	88	0	36	42
	92	0	05	06
	93	0	06	07
	94	0	05	06
	70	0	36	42
	59	0	19	22
	60	0	02	02
	8	0	43	50
	7	0	05	06
	6	0	17	20
	5	0	14	16
	402	0	36	43
	398	0	10	12
	10	0	33	39
	393	0	23	27
	394	0	59	69
	390	0	36	42
	386	0	03	04
	387	0	30	35
	384	0	11	13
	388	0	10	12
	95	0	00	15

[No. O-12016/142/83-Prod.]

कां.ग्रां. 1381.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन.के.ई.जेड. से एन.के.सी.एच. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन

के लिये एनद्राष्ट्र अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनद्राष्ट्र घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में द्वाबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि को नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 का इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

एन.के.ई. जेडू से एन.के.सी. तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात	जिला—अहमदाबाद	तालुका—विरमगाम
गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर एग्राई सेंटीयर
तेलवी	232	0 15 60

[सं. O-12016/23/84-प्रोड.]

S.O. 1381.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEZ to NKCH in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Mukarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from NKEZ to NKCH

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hect-are	Arc	Centi-arc
Telavi	232	0	15	60

[No. O-12016/23/84-Prod.]

कां.आं. 1382.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के कर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.आं.सं. 4373 तारीख 17-11-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिश्चित

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिश्चित भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्राष्ट्र घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिश्चित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्राष्ट्र अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

राज्य : गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : ओलपाड
गांव	श्लोक नं०	हेक्टेयर एग्राई सेंटीयर
आमला	95	0 31 34
	92	0 41 30
	93	0 21 30
	87	0 31 05
	91 बी	0 07 65

[सं. O-12016/130/83-प्रोड.]

S.O. 1382.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 4373 dated 17-11-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka: Olpad

Village	Survey No.	Hect- are	Arc	Centi- are
Obhala	95	0	31	34
	92	0	44	30
	93	0	21	30
	87	0	31	05
	91/B	0	07	65

[No. O-12016/130/83-Prod.]

कां०आ० 1383.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन बिछाने में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां०आ०० 4156 तारीख 25-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम अधिकांश ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका : ओलपाड		
गांव	सर्वे०	हेक्टेयर ए०आर० मंटीयर		
1	2	3	4	5
कनाड	125	0	22	27
	कांटे ट्रैक	0	06	07
	126	0	26	30
	128	0	88	02
	130	0	23	27
	135	0	51	60
	134	0	08	09
	132	0	74	87
	144	0	06	07
	कांटे ट्रैक	0	00	60
	201	0	08	00
	183	0	33	39
	200	0	02	02

1	2	3	4	5
	184	0	40	47
	185	0	32	37
	176	0	06	07
	175/1	0	16	19
	175/बी	0	15	18
	173	0	08	09
	174	0	20	23
	172	0	03	04
	164	0	64	75
	163	0	21	28

[मं० O-12016/128/83-प्रोड०]

S.O. 1383.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 4156 dated 25-10-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hec- tare	Arc	Centi- tiare
Kanad	125	0	22	27
	Cart Track	0	06	07
	126	0	26	30
	128	0	88	02
	130	0	23	27
	135	0	51	60
	134	0	08	09
	132	0	74	87
	144	0	06	07
	Cart Track	0	00	60
	201	0	08	00
	183	0	33	39
	200	0	02	02
	184	0	40	47
	185	0	32	37
	176	0	06	07

1	2	3	4	5
	175/A	0	16	19
	175/B	0	15	18
	173	0	08	09
	174	0	20	23
	172	0	03	04
	164	0	64	75
	163	0	24	28

[No. O-12016/128/83-Prod.]

का० आ० 1384.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० डी० ए० ए० से एस० डी० ए० डी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आशेष मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

कुआं नं० एस० डी० ए० ए० से एस० डी० ए० डी० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

गांव	प्लॉक नं०	हेक्टेअर	एअरार्ड	सेन्टीअर
1	2	3	4	5
कुदादरा	213	0	12	90
	209	0	14	95
	208	0	11	05
	200	0	07	80
	197	0	12	61
	198	0	21	45
	187	0	18	98
	183	0	10	40
	184	0	05	40
	185	0	03	25
	186	0	04	68

[सं० O-12016/21/84-प्रोड०]

S.O. 1384.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDAA to SDAD in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## Pipeline From Well No. SDAA to SDAD

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kudadra	213	0	12	90
	209	0	14	95
	208	0	11	05
	200	0	07	80
	197	0	12	61
	198	0	21	45
	187	0	18	98
	183	0	10	40
	184	0	05	46
	185	0	03	25
	186	0	04	68

[No. O-12016/21/84-Prod.]

का० आ० 1385.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० डी० डब्ल्यू० (16) से एस० डी० डी० (25) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजनों के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आशेष मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

एस० बी० डब्ल्यू० (16) से एस० बी० (25) तक  
पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला एवं तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेटीयर
जागुदान	913	0	06	00
कार्ट ट्रैक		0	00	84
904		0	04	92
902/1		0	04	08
901/1		0	04	56
900		0	04	92
898/3		0	09	00
898/1		0	07	82
897		0	11	28
896		0	08	16

[सं० O-12016/22/84-प्रोड०]

S.O. 1385.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest for the transport of petroleum from SBW(16) to SDB(25) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline From SBW (16) to S. D. B. (25)

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Jagudan	913	0	06	00
	Cart track	0	00	84
	904	0	04	92
	902/1	0	04	08
	901/1	0	04	56
	900	0	04	92
	898/3	0	09	00
	898/1	0	07	82
	897	0	11	28
	896	0	08	16

[No. O-12016/22/84-Prod.]

का०आ० 1316.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ० 2757 तारीख 13-6-83

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन मरगादर को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

विरमगाम से सी० टी० एफ० कलोन तक पाइपलाइन बिछाने के लिए  
राज्य:—गुजरात जिला:—मेहसाना ता:—कडी

गांव	सर्वे० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेटीयर
वायलू	490	0	01	35
	503	0	20	85
	502	0	18	75
	501/ए०	0	00	30
	501/बी०	0	14	70
	508	0	20	55
	537	0	09	30
	536/1	0	10	50
	536/2	0	04	35
	535/1	0	00	15
	601	0	03	60
	602	0	08	70
	603	0	05	55
	609	0	05	25
	612	0	00	15
	611	0	04	20
	610	0	08	85
	618	0	12	90
	617	0	09	90
	660	0	11	25
	661/1	0	09	00
	661/2	0	09	00
	658	0	21	15
	649	0	07	80
	650	0	13	20
	652	0	11	55
	653/1	0	03	00
	653/2	0	03	00
	653/3	0	05	30

1	2	3	4	5
	651/2	0	01	00
	751	0	00	90
	762/1	0	11	10
	757/B	0	06	00
	757/A/P	0	06	60
	757/A/P	0	13	95
	755	0	08	85
	758	0	14	85
	775/1/A/P	0	10	10
	844	0	00	90
	843	0	08	80
	856	0	07	20
	857	0	01	80
	855	0	03	75
	858	0	14	25
	859	0	03	00
	849/1	0	03	75
	863/1	0	01	87
	1031	0	24	98
	1030	0	04	50
	1036/1	0	02	85
	1036/2	0	07	65
	1037	0	00	15
	1035	0	12	60
	1039	0	07	50
	1050	0	12	75
	1051	0	07	50
	1121	0	10	25
	1122	0	06	00
	1123/2	0	06	00
	1123/3	0	08	20
	1123/1	0	00	20
	1124	0	08	10
	1144	0	14	25
	1144/1	0	07	65
	1144/2	0	06	45
	1145	0	05	00
	1146	0	12	00
	1161	0	02	25

[No. O-12016/44/83-Prod.]

S.O. 1386.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 2757 dated 13-6-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline From Virangam to C.T.F. Kalol					
State : Gujarat		District Mehsana		Taluka : Kadi	
Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare	
1	2	3	4	5	6
BAVLU	490		0	01	35
	503		0	20	85
	502		0	18	75
	501/A		0	00	30
	501/B		0	14	70
	508		0	20	55
	537		0	09	30
	536/1		0	10	50
	536/2		0	04	35
	535/1		0	00	15
	601		0	03	60
	602		0	08	70
	603		0	05	55
	609		0	05	25
	612		0	03	15
	611		0	04	20
	610		0	08	85
	618		0	12	90
	617		0	09	90
	660		0	11	25
	661/1		0	09	00
	661/2		0	09	00
	658		0	21	15
	649		0	07	80
	650		0	13	20
	652		0	11	55
	653/1		0	03	00
	653/2		0	03	00
	653/3		0	05	30
	651/2		0	01	00
	751		0	09	90
	762/1		0	11	10
	757/B		0	06	00
	757/A/P		0	06	60
	757/A/P		0	13	95
	755		0	08	85
	758		0	14	85
	775/1/A/P		0	10	10
	844		0	00	90
	843		0	08	80
	856		0	07	20
	857		0	01	80
	855		0	03	75
	858		0	14	25
	859		0	03	00
	849/1		0	03	75
	863/1		0	01	87
	1031		0	24	9
	1030		0	04	50 <sup>8</sup>
	1036/1		0	02	85
	1036/2		0	07	65
	1037		0	00	15
	1035		0	12	60
	1039		0	07	50
	1050		0	12	75
	1051		0	07	50
	1121		0	10	25
	1122		0	06	00
	1123/2		0	06	00



1	2	3	4	5
	1123/3	0	08	20
	1123/1	0	00	20
	1124	0	08	10
	1144	0	14	25
	1144/1	0	07	65
	1144/2	0	06	45
	1145	0	06	00
	1146	0	12	00
	1161	0	02	25

[No. O-12016/44/83 Prod.]

का० प्रा० 1987:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूना तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पाइप लाइन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० बम्बई द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्णतः कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये सक्षम प्राधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई—पूर्व पाइप लाइन प्रोजेक्ट फ्युअल रिकॉयनरीज कारिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाले हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मौफत।

## अनुसूची

पाइप लाइन मानखुर्द गांव से,  
तालुका: कुर्ला, जिला: बम्बई, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा	क्षेत्रफल हेक्टेयर ऐंटर
मानखुर्द	138 का भाग	—	00 = 02
—	150	—	00 = 02.25
—	245	—	00 = 04

[सं० 1387/12016/19/84-प्रॉड]

S.O. 1387.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipe-line and that said Pipe-line is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipe-line it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of petroleum and Minerals Pipe-lines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

69 GI/84—4

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

## SCHEDULE

Pipeline from the Village: Mankhurd, Taluka Kurla,  
Dist: Bombay, Maharashtra

Village	Survey No.	Hisra	Area	
			H.	R.
Mankhurd	138 Part	—	00	= 02
-do-	150	—	00	= 02.25
-do-	245	—	00	= 04

[No.-O-12016/19/84-Prod.]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984—

का० प्रा० 1388:—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्णतः कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मौफत।

## अनुसूची

वायर बेड और एनोड बेड बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला: मच्छेड़ा तालुका: खड्डा

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
बोडज	219	0	01	20

[सं० O-12016/13/84-प्रॉड]

New Delhi, 12th April, 1984

S.O. 1388.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for wire bed and anode bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition or Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### RIGHT OF USER FOR WIREBED AND ANODE BED

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Kheda

Village	Survey No.	Hectare	Ars	Centiar
Bidaj	219	0	01	20

[No. O-12016/13/84-Prod]

का०आ० 1389.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ०सं० 4374 तारीख 18-11-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में ग्रहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं के मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

कवोल-14 से जी०जी०एम-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	आर.	में से
भोयनरगेड	143	0	04	35
	144/1	0	12	75
	145	0	19	50
	146	0	15	30
	147/2	0	04	50
	147/1	0	10	05
	148/1	0	13	00
	148/2A	0	09	30

[सं० O-12016/136/83-प्रोड०]

S.O. 1389.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 4376 dated 18-11-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition or Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM KAUL 44 TO GGSII

State : Gujarat	District & Taluka : Gandhinagar			
Village	Survey No.	Hectare	Ars	Centiar
Bhoyan	143	0	04	35
Ratnod	144/1	0	12	75
	145	0	19	50
	146	0	15	30
	147/2	0	04	50
	147/1	0	10	05
	148/1	0	13	00
	148/2A	0	09	30

[No. O-12016/136/83-Prod]

का०आ० 1390.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी०जी०एम-II से श्री जी०जी०एम-II बिराज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में रहित कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह तह चाहता है कि उसकी मुनबाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

कृप नं० वी०जे०डी०जी० से जी० जी० ए० विराज तक पाईप लाईन  
बिछाने के लिए।

गाँव	सर्वेक्षण	हेक्टेयर	एयर	सेंटिमीटर
नानी कडी	187/2	0	07	65
	187/1	0	02	10
	185/1	0	11	40
	190/12	0	07	30
	190/11	0	06	90
	190/10	0	06	69
	190/9	0	06	00
	190/4	0	08	49

[सं० O-12016/6/84-प्रोड.]

पी०के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S.O. 1390.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from VJDG to GGS VIRAJ in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

PIPELINE FROM WELI NO. VJDG TO GGS VIRAJ  
STATE : GUJARAT DISTRICT : MEHSANA  
TALUKA : KADI

Village	Survey	Hectare	Are	Centiare
NANI KADI	187/2	0	07	65
	187/1	0	02	10
	185/1	0	11	40
	190/12	0	07	30
	190/11	0	06	90
	190/10	0	06	69
	190/9	0	06	00
	190/4	0	08	49

[No. O-12016/6/84-Prod.]

P. K. RAGAJOPALN, Desk Officer

## पर्यटन और भागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

का० आ० 1391.—अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पर्यटन के महानिदेशक, श्री एन० के० सेनगुप्ता को श्री जी० एन० मेहरा के स्थान पर तत्काल ही तथा अगले आदेशों तक, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंशबालिक सदस्य नियुक्त करती है।

[ए० सी० 24012/1/82-ए० (विन-I)]

आर० एन० भार्ताव, अवसर मन्त्रि

## MINISTRY OF TOURISM &amp; CIVIL AVIATION

New Delhi, the 11th April, 1984

S.O. 1391.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 3 of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri N. K. Sengupta, Director General of Tourism as a part-time Member of the International Airport Authority of India with immediate effect vice Shri G. N. Mehra until further orders.

[AV.24012/1/82-AA(F, II)]

R. N. BHARGAVA, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1984

का. आ. 1392.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मंत्रालय टेलीफोन कोड में दिनांक 1-5-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[संख्या 5-8/84]

यो. रा. भसीन, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&amp;T Board)

New Delhi, the 19th April, 1984

S.O. 1392.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-5-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Metpalli Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-8/84-PHB]

Y. R. BHASIN, Asstt. Director General (PHB)

## MINISTRY OF LABOUR &amp; REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 12th April, 1984

S.O. 1393.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur and their workmen which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-3/1980

## REFERENCE :

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi  
Notification No. L-12011/32/79-D-II(A), dated 4th August, 1980.

In the matter of an Industrial Dispute  
BETWEEN

Shri Kailash Singh represented by the General Secretary, Rajasthan Bank Employees Union, Jodhpur.

AND

The General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur,  
S. M. S. Highway, Jaipur.

## PRESENT :

For the Union : Shri Man Singh  
For the Management : Shri P. C. Jain.  
Date of Award : 29th May, 1983.

## AWARD

The Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-12011/32/79-D-II(A) dated 4-8-1980 has made the following reference for adjudication:—

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, S. M. S. Highway, Head Office Jaipur in relation to its Public Park Branch at Bikaner in denying to Shri Kailash Singh who attended to the Bank's cycle stand at the said branch, wages and allowances to which other subordinate staff are entitled, with effect from April, 22nd, 1976 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. As the very terms of reference will indicate the question for adjudication is as to whether Shri Kailash Singh who attends to the cycle stand of the Bank at its branch at public park, Bikaner is an employee of the Bank and if so belongs to its subordinate staff. In case answer shall be in favour of Shri Kailash Singh then consequential relief to be granted to him will be considered.

3. There is no written order either appointing Shri Kailash Singh or giving a contract of cycle stand to him. Annexure R-1 is an application of Shri Kailash Singh and a bare reading of it will show that as the contractor who had the contract of banks cycle stand had left, Kailash Singh requested that the contract be given to him at the same terms and conditions as held previously. On this application of Shri Kailash Singh the Bank paid Rs. 110 per month from April 1st, 1976 to December 25th 1978. The amount was increased to Rs. 150 per month w.e.f. December 26th 1978. The case of Shri Kailash Singh is that his work is of keeping watch on the cycle stand and the work is of a regular and permanent nature. The provisions of Bank Awards and Bipartite Settlements are applicable and Shri Kailash Singh is entitled to the same wages which are being paid to the subordinate staff of the Bank. In short his claim is that he is an employee and not an independent contractor as claimed by the bank.

4. In reply, bank has taken a clear stand that Shri Kailash Singh is an independent contractor. He never raised any objection in regard to his status as such. He is not an employee of the bank as claimed by him and is not entitled for the wages and allowances paid to the subordinate staff of the bank. It is also the case of the bank that Shri Kailash Singh was neither marking any attendance or nor he required to do so. He never applied for any leave nor he was required to do so. He could have left the place of working at his own will without any permission and thus by nature of the contract he is an independent contractor.

5. In support of his case Shri Kailash Singh filed his own affidavit, on behalf of the Bank affidavit of Shri P. S. Mathur, Manager, Finance and Accounts in the Bank has been filed. The deponents were cross examined on their affidavits.

6. I have heard the learned counsel for the parties. The first and foremost question is to be decided is whether Shri Kailash Singh is an employee of the bank as claimed by him or an independent contractor, a stand taken by the bank? As already stated earlier the terms of alleged employment of Shri Kailash Singh, have not been spelt-out in any document. But from whatever material has come on record the terms become quite clear. There is a cycle stand meant for the employees of the bank at Bikaner and is situated in the premises of the bank. The employees keep their cycles on the cycle stand. Shri Kailash Singh was paid Rs. 110 p.m., which amount was later on increased as 150 p.m. The manner in which Shri Kailash Singh is to keep a watch on the cycles of the employees is entirely his look out and the bank or its officer have no right to indicate as to in what manner Shri Kailash Singh discharged his duties. Shri Kailash Singh does not mark his presence nor his presence is marked by anybody else. He does not apply for leave nor any is sanctioned. He may either himself do the work or depute somebody to do the work. Shri Kailash Singh admits in his cross examination on his affidavit that his attendance is not marked in the bank, he has never taken any leave from the bank and even during illness it is he who looks after the work. Shri P. S. Mathur for the bank states that it is not the duty of the bank to supervise the working of Shri Kailash Singh so far as the cycle stand is concerned. In case Shri Kailash Singh does not come then he depute somebody else to look look after the work. There is also no dispute that the working hours are 9-30 a.m. to 5-15 p.m. Thus it can be said that there

is no control of the bank in the manner in which a watch is to be kept over the cycles kept in cycle stand and it is also not necessary that the work should be done personally by Shri Kailash Singh, he can depute somebody else.

7. The question is as to whether from the above facts it is a contract of service or contract for service? Before I take up this point, it is necessary to refer to one argument of Shri P. C. Jain for the bank that Shri Kailash Singh is not a workman within the meaning of Section 2(S) of the Industrial Disputes Act, 1947 (for short the Act hereinafter). The argument of Mr. Jain in this connection is that only four categories of the persons are workmen within the meaning of Section 2(S) namely to do any (i) skilled (ii) unskilled manual (iii) supervisory (iv) technical or clerical work for hire in an industry. It also includes apprentice. So according to Mr. Jain for the bank, that Shri Kailash Singh does not fall under any of the above referred to categories. He does not do any manual work and merely because he does unskilled work, unless the work done by him is unskilled manual he will not be a workman within the meaning of aforesaid section of the Act. According to him as per the material on record the only work which was done by Shri Kailash Singh was that he was keeping a watch on the cycles kept on the cycle stand, which does not involve any manual work. But I do not agree with this submission of Mr. Jain as from the reply of the bank itself it becomes clear that not only Shri Kailash Singh keeps a watch on the cycles but he also parks them. Parking can only be by handling a cycle and one who handles a cycle, he keeps it at a proper place, in the process of parking he does a manual work. In para 3(i) of the reply it has been clearly stated on behalf of the bank that Shri Kailash Singh was entrusted with the security and the arrangement for parking of the cycles of the members of the staff at the public park, Bikaner branch. Again it is stated at para 3 in the same sub para that Shri Kailash Singh was engaged to undertake the security and parking of the cycles and in execution of this work he was not under the supervision and control of the management of bank. Thus from the reply it becomes clear that he was doing unskilled manual work and as such he was a workman within the meaning of Section 2(S) of the Act.

8. Now I take the submission of Mr. Man Singh, learned counsel for the union who is espousing the cause of Shri Kailash Singh, the worker, that the control and supervision by the employer is no more a decisive factor in reaching to the conclusion as to whether there is relationship of employer and employee or not. According to him the working hours were from 9-30 a.m. to 5-15 p.m. and during these hours Shri Kailash Singh was to keep a watch over the cycles stand where the cycles of the employees were kept. He was thus rendering services to the bank for which he was paid monthly emoluments and as such there was relationship of employer and employee and he was not an independent contractor. In support of his submission Mr. Man Singh has placed reliance on (1) Canara Bank Vs. Appellate Authority FIR 1977(35) 260, (2) Silver Jubilee Tailoring House Vs. Chief Inspector of Shops and Establishments FIR 1973 (27) 351, (3) Hussainbhai, Calicut Vs. The Alath Factory Textilal, Union Kozhikode, FLR 1978 (37) 137 and (4) Randhir Singh Vs Union of India 1982 (1) S.L.J. 490.

9. (1) was a case under Kerala Shops and Establishments Act, 1960. The document evidencing the terms of employment of the second respondent clearly provided that the second respondent is not an employee but only an independent contractor. There was a stipulation to pay 12 paise per loan, there was also a provisions that the second respondent may engage himself in his own business or trade and that the contractor was to be terminated by one months notice in writing. A notice was issued under clause 13 of the document to the second respondent intimating termination of his service. The question arose as to whether the second respondent was an employee of the bank or only an independent contractor. It was held that even granting that the second respondent is an independent contractor under the document and even conceding that he was at liberty to work elsewhere and he was not bound to be with the Canara Bank always during the office hours, the second respondent is entitled to benefits under the Kerala Shops

and Establishments Act, 1960. The learned Judges did not say anything on merits as to whether the second employee was an employee or not and observed in para 22 "On merits I may state that the Appellate Authority has discussed the matter in detail in Ex. P6 and found that the second respondent is an employee under the bank on the evidence and material available and the nature of work that the second respondent was doing in the Canara Bank. It is well settled that the jurisdiction of this Court under Article 226 while dealing with the conclusions of a Tribunal like the appellate authority in the case, is limited and this Court will be slow in interfering with those conclusions unless this Court is satisfied that the conclusions are unreasonable or that there is a clear error of law committed by the Tribunal." Thus it will be clear that no independent conclusions were reached as the judges simply refused to interfere. In (2) which was a case of a worker working in a tailoring shop, all the workers were paid on piece-rate basis. They generally attended the shops every day if there was work. The rate of wages paid to the workers was not uniform and depended upon the skill of the worker and the nature of work. After the cloth was cut and was given for stitching to a worker he was told how he should stitch it. If the worker did not stitch it according to the instructions, the employer rejected the work and generally asked the worker to re-stitch the same. When the work was not done by the worker according to the instructions generally no further work would be given to him. If there was no work the employee was free to leave the shop before the shop closed or if the worker does not want to go for work to the shop on a day he did not make any application for leave, nor there was any obligation on his part to inform the employer. On the facts of that case it was held that there was relationship of employer and employee. It will be clear that one of the tests was that the worker was to stitch the cloth in accordance with the instructions of the employer who could reject the work and could ask the worker to re-stitch the same. Thus these cases have no application to the present case. In (3) the tests for determination of relationship of employer and employee have been stated: It was a case of workers producing goods by the labour or rendering services. The employer had not only economic control but also control over skill and subsistence. Under those circumstances it was held that there was relationship of employer and employee. Case No. (4) is a case laying down law that there should be equal pay for equal work. It is a case of drivers. The question of equal pay for equal work will only arise in case of employees who are discharging similar nature of duties. In case one is not an employee the principle enunciated there will not be attracted.

10. From the above authorities it will be clear that various tests have been laid down to determine as to whether there is relationship of employer and employee or whether one is an independent contractor. It will depend on facts and circumstances of each case as to whether there is contract for service or contract of service. In case there is contract for service then one will be an independent contractor and when there is, contract of service there will be relationship of employer and employee. The facts of all cases are different and any observations made in any of the ruling are to be read in the contexts of facts of the very case. On behalf of the bank Mr. Jain in support of his submission that it was a contract for service and not contract of service has placed reliance on *Dhrangadhra Chemical Works Ltd. vs. State of Saurashtra* SCJ (32)2022. Their lordships laid down in the aforesaid ruling that the broad distinction between a workman and an independent contractor lies in this that while the former agrees to work, the later agrees to get others work. They also observed that what determines whether a person is a workman or independent contractor is whether he has agreed to work personally or not. If he has, then he is a workman and the fact that he takes assistance from other persons would not affect his status. It was also held by their lordships that a distinction is always drawn between a contract for service and a contract of service and that distinction is put in this way. "In the one case the master can order or require what is to be done while in the other case he cannot only order or require what is to be done but how itself it shall be done." It was observed that the principle which emerges from the authorities is that the prima facie test for determination of the relation-

ship between master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant not only in the matter of directing what work the servant is to do but also the manner in which he shall do his work. Hon'ble Supreme Court in later cases has observed that the control test is no more a decisive factor but is an important factor to determine as to whether there is relationship of employer and employee. The other case referred to by Mr. Jain is *Employers in relation to Punjab National Bank vs. Ghulan Dastgir* 1978 (1) LLJ, 212. It was a case of a driver employed by the Area Manager of Punjab National Bank in Calcutta and his salary was paid out of the personal allowance given to the Area Manager by the Bank. The matter was with regard to the termination of the services of the driver. Observing that there was nothing on record to indicate that the control and direction of the driver vested in the bank, the driver was included in the army of employees in the establishment of bank—it was held that there was no relationship of employer and employee between the driver and the bank.

11. In the instant case the facts have already been stated earlier. Shri Kailash Singh applied for and was appointed as a contractor to keep a watch over the cycles in the cycle stand of the bank. He could either do the work himself or the work could be done by somebody else on his behalf. Bank could not have asked him as to in what manner he is to keep a watch. To my mind it is only a contract for service and not a contract of service. Therefore, there was no relationship of employer and employee between Shri Kailash Singh and the Bank. There is no post of a watchman or a peon in the establishment of the bank to discharge the duties of keeping a watch on the cycle stand.

12. The question therefore, of treating Shri Kailash Singh as a member of the subordinate staff does not arise. That apart from the terms of reference which have been reproduced earlier the reference is not as to whether Shri Kailash Singh is a member of subordinate staff of the bank. The reference is only as to whether he is entitled to wages and allowances to which other subordinate staff are entitled.

13. It was submitted by Mr. Man Singh for the worker that the contract amount was raised from Rs. 110 to Rs. 150 p.m. in the year 1978 and now it is 1983 and therefore the amount should be increased but that is not a term of reference. That apart this Tribunal could have granted any relief in case there would have existed a relationship of employer and employee i.e. master and servant and as has been held, that he was an independent contractor the jurisdiction to grant any relief does not vest in this Tribunal.

14. In the result Shri Kailash Singh is not entitled to any relief from this Tribunal.

15. Let the Award be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act.

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer

[No. L-12011/32/79-D.II(A)]

S.O. 1394.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur and their workmen; which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-31/1982

#### REFERENCE :

Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi Notification No. L-12011/65/81-D.II(A) dated 25th August, 1982.

In the matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

Gramin Bank Employees Union, Jaipur.

AND

Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur.

PRESENT :

For the Union :

For the Management : Shri I. S. Singhvi.

Date of Award : 16th June, 1983

#### AWARD

The Central Government has made the following reference to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur in deducting Provident Fund Contribution of its employees at the rate of 6.25 per cent of their Basic Pay instead of at the rate of 8.33 per cent with effect from 1.11.1978 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. The case of the union who has espoused the cause of its workers, or employees of the bank is that the management of the Bank under the Circular dated December, 23rd 1978 had issued orders for deduction of Provident Fund @8.33%. The deductions at that rate were to be made on the basic wages of the employees. The above orders were later on amended by another circular dated August, 20th 1979 under which the Provident Fund was to be deducted @6.25% on basic wages plus other allowances excluding House Rent Allowance. According to the union this action of the management of the Bank is not in accordance with law because prior to amendment in the rate of Provident Fund deductions, no notice under Section 9-A of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (for short the Act hereinafter) was given. According to the union the provident fund has not been deducted @8.33% on basic wages plus other allowances excluding house rent allowance. The prayers made in the statement of claim on behalf of the union are (1) that provident fund should be deducted @8.33% on all allowances excluding house rent allowance; (2) that the difference of the amount of provident fund in accordance with the provident fund scheme after November 1st 1978 should be deposited by the management of the Bank and (3) that the management of the Bank should be punished for contravention of the provisions of the Act. Two other prayers have also been claimed which have no merit.

3. The Bank has filed its reply to the statement of claim of the union. The provisions of the Act were made applicable to the Bank w.e.f. November 1st 1978. As per the letter dated 6th November 1978 of the Regional Provident Fund Commissioner, Provident Fund @6.25% on the basic wages plus allowances minus House Rent Allowance was to be deducted. Prior to that there was no policy for deduction of provident fund in the Bank as such orders were passed for deduction of provident fund @8.13% of basic pay plus dearness pay plus special pay, if any. According to the Bank amendment in the rate of provident fund is in accordance with law and no notice under S. 9-A of the Act as alleged by the union is necessary.

4. I have heard the learned the parties and no evidence has been led by the parties.

5. A look at annexure 1, Circular of the Chairman of the Bank issued on December, 23rd 1978 and its reading will make it clear that the Board of Directors of the Bank had taken a decision to deduct provident fund @8.33% of basic pay commencing from the month of November, 1978 from the salary of all those staff members who had completed one year or more service as on 31st October, 1978 except in few cases where deduction was not warranted. Section 6 of the Act provides that the contribution which shall be paid by the employer to the Fund shall be six and a quarter per cent of the basic wages (dearness allowance and retaining allowance, if any) for the time being payable to each of the employees and the employee's contribution shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of him and may, if any employee so desires and if the scheme makes provision therefore, be

an amount not exceeding eight and one-third per cent of his basic wages (dearness allowance and retaining allowance (if any)). 'Basic wages' have been defined in S. 2(b) of the Act and mean all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave with wages in accordance with the terms of the contract of employment and which are paid or payable in cash to him but does not include (i) the cash value of any food concession (ii) any dearness allowance, house rent allowance, overtime allowance, bonus, commission or any other similar allowance payable to the employee in respect of his employment or of work done in such employment. It also does not include any present made by the employer. Thus under S. 6 of the Act the employer was required to contribute to the Fund six and a quarter per cent of the basic wages (dearness allowance and retaining allowance (if any)) for the time being in force. Whereas under the Circular dated 23rd December, 1978 the Board of Directors of the Bank had taken a decision to deduct provident fund @8.33% of basic pay only. Under another circular Annexure-2 dated August 20th, 1979 took a decision that provident fund contribution will be made @six and a quarter per cent of total emoluments excluding house rent allowance from and out of the salary payable to the employees' concerned. This was also effected w.e.f. November 1st, 1978. Thus the second circular appears to be in consonance with the provisions of S 6 of the Act. Earlier decision to deduct provident fund @8.33% appears to have been taken not under the Act but as per the practice prevalent in other commercial banks which as given out by Mr. Singhvi had created their own trust for the purpose. It is also given out by Mr. Singhvi that the request by the Bank to credit a trust similar to one created in other commercial banks was turned out by the Regional Provident Fund Commissioner, Jaipur.

6. Section 9-A of the Industrial Disputes Act, 1947 provides that no employer who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change:—(a) without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected; or (b) within twenty one days of giving such notice. No notice is required for effecting any such change where the same is effected pursuant of any settlement, award or decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950 (48 of 1950); or, where the workmen likely to be affected by the change are persons to whom the Fundamental and Supplementary Rules, Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, Civil Services (Temporary Service) Rules, Revised Leave Rules, etc. as given in proviso (b) to S. 9-A of the Act. One of the matters specified in Fourth Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 will show that it relates to contribution paid, or payable, by the employer to any provident fund or pension fund or for the benefit of the workmen under any law for the time being in force. Under the Act the provident fund @six and a quarter per cent of the basic wages on dearness allowance and retaining allowance, if any were to be contributed by the employer and the employee's contribution was also to be equal payable by the employer in respect of him. Only if any employee so desires and the scheme makes provision thereof, an amount not exceeding eight and one third per cent of basic wages and D.A. and R.A. if any could be contributed by the employee as his share to the provident fund. Thus there is no provision under the Act for contributing @8.33 per cent of the basic wages of an employee and dearness allowance and retaining allowance, if any. It can, therefore, be said that in the IV Schedule to the Act of 1947, provident fund @8.33 per cent of basic wages was ordered to be contributed by the Board of Directors of the Bank under the earlier circular dated December 23rd, 1978. Therefore, when under the later circular dated 20th August, 1979 the management of the Bank decided to contribute provident fund @6 and a quarter per cent of the basic wages plus dearness allowance w.e.f. November 1st, 1978 when the provisions of the Act were made applicable to it. No notice under S. 9-A of the Act of 1947 to the workers was necessary.

7. I am, therefore, of the opinion that the action of the Management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank Jaipur in deducting provident fund contribution of his employees @ six and a quarter per cent of their basic pay including D.A. w.e.f. November, 1978 instead of @8.33% is justified. The workers are not entitled to any relief.

8. Let this Award and its requisite copies be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act of 1947.

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer  
[No. L-12011/65/81-D.II(A)]

SO 1395.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० बी० आई० टी० 5/80—

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एन०-12012/159/79-डी-II दिनांक 7-10-80

श्री शिव कुमार विरानी पुत्र श्री हन्दर मल विरानी परधियन का मोहल्ला पो०ओ० भिवानी, जिला अजमेर

—श्रमिक पक्ष

बनाम

रीजनल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर

—नियोजक पक्ष

उपस्थिति

श्रमिक पक्ष की ओर से: श्री बी०एल० समवरिया  
नियोजक पक्ष की ओर से: श्री पारम कुंहाड़  
दिनांक अर्वाह: 9-5-83

अर्वाह

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते निपटारा अपनी अधिसूचना सं० एन-12012/159/79-डी II-ए दिनांक 7-10-80 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत भेजा है:

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, regional Office, Jaipur in terminating the services of Shri Shiv Kumar Virani, Fatesh-cum-Peon with effect from 22-2-79 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. यह विवाद केन्द्र सरकार द्वारा श्री शिवकुमार विरानी बैंक आफ बड़ौदा, रीजनल ऑफिस की सेवा मुक्ति से संबंधित है।

3. श्रमिक श्री शिव कुमार विरानी ने अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम वाले में यह अंकित किया है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 25-5-77 को फरास कम पिओन के पद पर च०श्रे०क० की हैमियत से रीजनल मैनेजर, जयपुर बैंक आफ बड़ौदा द्वारा की गई थी। उनकी सेवा अवधि समय समय पर बढ़ाई गई एवं सक्षम अधिकारी जिन्होंने नियुक्ति की वह रीजनल मैनेजर थे। श्रमिक के अनुसार उनकी सेवा मुक्ति का आदेश सेवा से हटाये जाने मात्र नहीं है बल्कि इस कारण सेवा मुक्ति की गई क्योंकि उसने ब्रांच मैनेजर पारसोनी के यहाँ घरेलू काम करने से मना कर दिया। श्रमिक द्वारा उसकी सेवा मुक्ति के आदेश को मुख्यतः निम्न आधारों पर चुनौती दी गई है वे यह हैं:

1. पत्र दिनांक 21-2-79 पर रीजनल मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर नहीं विगो गये हैं।

2. सेवा मुक्ति का आदेश गद्दभायी रूप से पारित नहीं किया गया है एवं श्रमिक ने मैनेजर के घर पर कार्य नहीं किया इस कारण दुर्भावना पूर्ण तरीके से पारित किया गया है।

4. विपक्षी की ओर से स्टेटमेंट आफ क्लेम का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अस्वीकार किया गया है कि ब्रांच मैनेजर के घर पर काम न करने के कारण श्रमिक की सेवा समाप्त की गई है। विपक्षी के अनुसार श्रमिक की नियुक्ति फरास कम पिओन के पद पर परीक्षा अवधि पर की गई थी, एवं परीक्षा का नाम से उसका कार्य संतोषप्रद नहीं था इसलिए उसकी सेवाये समाप्त कर दी गई। यह स्वीकार नहीं किया गया है कि श्रमिक की नियुक्ति रीजनल मैनेजर द्वारा की गई बल्कि विपक्षी के अनुसार श्रमिक ने गारमोनी की शाखा में दिनांक 25-5-78 को इम्प्टी जॉइन की। विपक्षी ने अनुसार मैनेजर के घर पर घरेलू काम करने के जो लांछन लगाये गये हैं वह बेग हैं एवं उन्म आवश्यक तथ्य नहीं दिये गये हैं। विपक्षी के अनुसार श्रमिक की कार्य क्षाता दो मैनेजरों द्वारा देखी गई थी। इसलिए जो आरोप मैनेजर के खिलाफ लगाये गये हैं वह सही नहीं हैं। विपक्षी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि श्रमिक छुट्टी लेकर गया था बल्कि उनके अनुसार वह अपने कार्य से अनुपस्थित हो गया। श्रमिक का यह कहना कि वह टारफाईड से पीड़ित था, भी विपक्षी को स्वीकार नहीं है।

5. पक्षकारों ने शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं शपथ गृहिताओं ने प्रतिपादन भी किया है। श्रमिक की ओर से शिव कुमार विरानी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विपक्षी की ओर से नारायण भाई बानमकुन्द के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। पक्षकार ने कुछ निश्चित प्रमाणों का भी सहारा लिया है। जिनका भी अवलोकन कर लिया गया है।

6. विद्वान अधिवक्ता श्रमिक ने अपने यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि श्रमिक की नियुक्ति रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी अतः केवल रीजनल मैनेजर ही उनकी सेवाये समाप्त कर सकते थे। उनके अनुसार पत्र दिनांक 21-2-79 प्रदर्श डब्ल्यू-13 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होगा कि सेवा समाप्ति मैनेजर द्वारा की गई जबकि नियुक्ति रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी। नियुक्ति के संज्ञे में श्री समवरिया विद्वान अधिवक्ता श्रमिक ने प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिनांक 10-5-78 का हवाला दिया है। उनके अवलोकन से बिदित होता है कि श्री विरानी की नियुक्ति फरास कम पिओन के पद पर रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी। नियुक्ति पत्र के अंतर्गत परीक्षा अवधि छः मास थी एवं उस अवधि में एक माह का नोटिस अथवा नोटिस पर दिये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती थी। परीक्षा अवधि 25 नवम्बर मन् 1978 से तीन माह के लिए और बढ़ा दी गई। एवं उसकी सूचना रीजनल मैनेजर की हिदायत के अनुसार अभिस्टेड मैनेजर द्वारा की गई। यह अवधि 25 फरवरी मन् 1979 को समाप्त होती थी। दिनांक 21-2-79 को मैनेजर के पत्र द्वारा सेवाये तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी गई एवं एक माह का वेतन, एक माह का नोटिस पे की एवज में 385 रु० 10 पैसे बैंक शाखा से ली जाने की हिरासत दी गई। अतः सेवाये जो समाप्त की गई वह परीक्षा अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कन दी गई।

7. दिनांक 21-2-79 के पत्र, शिगोटे द्वारा की सेवा तुरन्त प्रभावी से समाप्त की गई के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उच्च अधिकारियों की हिदायत के अनुसार सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा रही है। श्री समवरिया विद्वान अधिवक्ता श्रमिक के अनुसार नियुक्ति रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी एवं परीक्षा अवधि में भी सेवा मुक्ति का आदेश अन्य के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता था जबकि ऐसा न किया जा कर ब्रांच मैनेजर द्वारा किया गया है इसलिए सेवा मुक्ति का आदेश अवधि से श्री समवरिया ने अपने इस तर्क के समर्थन में निम्न धितियाये का सहारा लिया है। वह ये हैं:



1. राम शरण शर्मा बनाम स्टेट आफ पंजाब (एम०सी०) 1967 एस० एल० आर० पेज 771।

2. पदम प्रसाद शर्मा बनाम एस० एल० टी० एवं अन्य, 1982 (1) आल इंडिया मजिस्ट्रेट्स जर्नल।

3. प्रीमियर टायर लिमिटेड बनाम बी० ए० अब्राहम उच्च न्यायालय केरल, 1976 एस० एल० जे० पेज 161 एवं

4. स्टेट आफ पंजाब बनाम प्रकाश सिंह (एम०सी०) 1975 (2) एस० एल० आर० पेज 85 का अवलम्ब लिया है।

8. उपरोक्त विनिश्चयों में से (1) में यह मत व्यक्त किया गया है कि जिस फॉर्म में सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है यह अंतिम नहीं है एवं यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से न्यायालय को संतोष हो जावे कि इसअमल में वह आदेश डिगमिसल का आदेश है तो न्यायालय इस आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 311(2) की पालना नहीं की गई के आदेश को अवैध घोषित कर सकती है। (2) इसविनिश्चय में यह मत व्यक्त किया है कि यदि किसी ऐसे कर्मचारी, जो कि परीक्षा पर हों, की सेवा मुक्ति का आदेश सेवा से डिगमिसल अथवा स्वयं का हो तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 311 लागू होगा। (3) विनिश्चय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शब्द जो सेवा मुक्ति के आदेश में प्रयोग किये गये हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता एवं न्यायालय को यह देखना चाहिए कि आदेश दुर्भावना-पूर्वक पारित किया गया है अथवा नहीं। (4) विनिश्चय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि ऐसा कर्मचारी जो परीक्षा पर हों की सेवा मुक्ति का आदेश दंड स्वरूप पारित किया जाता है तो आर्टिकल 311 भारतीय संविधान लागू होगा। उनमें को विश्वास नहीं हो सकता कि सेवा मुक्ति का आदेश केवल उसी द्वारा पारित किया जा सकता है जिस अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई हो अथवा जो अधिकारी सक्षम अधिकारी हो विपक्षी की ओर से कुछ लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं यह दिखाने के लिए कि परीक्षा काल में सेवा से हटाये जाने का आदेश रोजनल मैनेजर द्वारा ही पारित किया गया था एवं न ही रोजनल मैनेजर के आदेश की पालना में श्रमिक को उस आदेश को केवल सूचना मात्र ही दी। जो पत्रादि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं उनके अवलोकन से यह विवृत होता है कि परीक्षा अवधि में श्री वीराणी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया इसलिए परीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले दिनांक 21-2-79 का सेवा मुक्ति का आदेश उच्च अधिकारी के आदेश की पालना में मैनेजर ने श्री वीराणी को दिया। 19 फरवरी 1981 का रोजनल मैनेजर का एक आदेश है, जो उनके द्वारा मैनेजर बैंक आफ बड़ोदा पारसीनी को भेजा गया था यह प्रदर्श एम-5 है। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि श्री वीराणी की सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायें एवं एक माह के नोटिस की एवज में उसे एक महीना की पे एवं अलाउन्स दे दिया जाय। उस पत्र के साथ उस पत्र का प्रारूप (ड्राफ्ट) भी भेजा गया जो श्री वीराणी को दिया जाना था। मैनेजर ने उसकी पालना में दिनांक 21-2-79 को श्री वीराणी को सूचित कर दिया कि उसकी सेवायें उच्च अधिकारी के आदेश के अंतर्गत तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा रही हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि श्री वीराणी की सेवायें परीक्षा अवधि में तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय रोजनल मैनेजर द्वारा, जिसके द्वारा कि नियुक्ति की गई थी, लिया गया एवं ब्रांच मैनेजर ने केवल उसकी सूचना ही वीराणी को दी। श्री समदर्शिका विधान अधिकांश श्रमिक ऐसा कानून नहीं बना केस कि चाहे निर्णय सेवा समाप्ति का सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया हो परन्तु उस निर्णय की सूचना भी सक्षम अधिकारी द्वारा ही दी जानी चाहिए थी न कि उनके अधीनस्थ किसी कर्मचारी द्वारा। अतः जब हम संतुष्ट हैं कि परीक्षा अवधि में सेवा समाप्ति का आदेश रोजनल मैनेजर, जिसके द्वारा नियुक्ति की गई, द्वारा ही पारित किया गया, केवल इसी कारण कि उसकी सूचना मैनेजर द्वारा दी गई, यह नहीं कहा जा सकता

कि सेवा समाप्ति का आदेश निश्चित पारित नहीं किया गया है अथवा अवैधानिक है। हम विस्तृत रूप में आगे बताएंगे कि परीक्षा अवधि में सेवा मुक्ति का आदेश दंड स्वरूप पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता। यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि यह सिद्ध नहीं है कि घरेलू काम करने के लिए वीराणी से मैनेजर द्वारा कहा गया हो और उसके काम न करने पर सेवा मुक्ति का आदेश पारित कर दिया गया।

9. श्रमिक श्री वीराणी ने शपथ पत्र में यह अवश्य कहा है कि उनके द्वारा कार्यालय समय से पूर्व एवं कार्यालय समय के बाद शाखा व्यवस्थापक के घर जाकर उनके निजी व घरेलू कार्य न करने पर दुर्भावना से प्रेरित हो कर सेवा पृथक्कीकरण का आदेश पारित किया। उनके अनुसार उनकी नियुक्ति के समय पारसीनी से मैनेजर ब्रांच बाल मुकुन्द शर्मा थे। उनके अनुसार पारसीनी से नियुक्ति होने के तीन महीने बाद में उन्होंने घरेलू काम के लिए कहा। उन्होंने छः महीने तक काम किया एवं छः महीने तक काम करने के बाद उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं की एवं यूनियन में भी शिकायत नहीं की। उनके अनुसार केवल शर्मा ही मैनेजर थे कोई दूसरा व्यक्ति मैनेजर नहीं था। विपक्षी की ओर से श्री बाल मुकुन्द शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उनसे प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कभी भी श्रमिक से घर पर काम करने के लिए कहा हो। यदि उनके कथन को विपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित प्रमाणों के साथ देखा जावे तो स्पष्ट होगा कि श्री वीराणी का यह कहना कि घरेलू काम न करने के कारण दुर्भावनापूर्ण उसकी सेवायें समाप्त की गई हैं सही प्रतीत नहीं होता। वीराणी के पिता द्वारा एक पत्र ब्रांच मैनेजर को लिखा गया था जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि वीराणी को छुट्टी दी जावे क्योंकि उनके कैरियर का प्रश्न है। श्री वीराणी के अनुसार उनमें छः माह तक कार्य किया तब तक तो कोई शिकायत नहीं थी परन्तु दिनांक 16-10-68 कोणाखा में नोटि से स्पष्ट होता है कि उसका काम तब भी संतोषप्रद नहीं था। श्री वीराणी ने कभी भी यह शिकायत नहीं की कि उसके द्वारा उसमें घरेलू काम लिया जा रहा है अथवा उस पर दबाव डाला जा रहा है नहीं अपने अधिकारी को न ही अपनी यूनियन को। अतः श्री वीराणी यह सिद्ध नहीं कर सके कि उनके द्वारा घरेलू कार्य न करने के कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर ब्रांच मैनेजर ने सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया। हम यह कह चुके हैं कि सेवा मुक्ति का आदेश रोजनल मैनेजर द्वारा ही पारित किया गया था न कि ब्रांच मैनेजर के द्वारा एवं रोजनल मैनेजर के विश्वास वीराणी की कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि वह उसमें नाराज था एवं दुष्टेयता से प्रभावित होकर परीक्षा अवधि में सेवा समाप्ति की गई। परीक्षा अवधि में यदि किसी कर्मचारी का काम संतोषप्रद नहीं रहता है तो उसकी सेवा समाप्ति की जा सकती है। श्री वीराणी के नियुक्ति पत्र में यह शर्त थी, कि उसकी सेवायें एक माह का नोटिस अथवा एक माह का नोटिस पे देकर समाप्ति की जा सकती हैं अतः हमारे विचार से यह नहीं कहा जा सकता कि बैंक आफ बड़ोदा के व्यवस्थापक तथा रोजनल अधिस द्वारा श्री वीराणी की सेवायें दिनांक 22-2-79 से समाप्ति करना अनुचित एवं अवैध है। हमारे विचार से श्री वीराणी कोई ग़लत पाने का अधिकारी नहीं है। यह अवार्ड पारित कर केन्द्र सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जावे।

महेश भूषण शर्मा, न्यायाधीश

[सं० एल० 12012/159/79-ड-II(ए)]

S.O 1396.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.



केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस० नं० सी० आई० टी० 2/1980.

केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : एल० 12011/112/78-डी II दिनांक 2-7-80

श्री मोहन दान एवं अन्य माफत राजस्थान बैंक कर्मचारी संघ, जयपुर।

—श्रमिक गण

बर्नाम

दी जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ब्रीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर।

उपस्थिति —नियोजक गण

श्रमिक गण की ओर से : श्री मान सिंह  
नियोजक पक्ष की ओर से : श्री मनोज शर्मा  
दिनांक प्रकाशित : 3-5-83

प्रकाशित

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते निपटारा प्रपनी अधिसूचना सं० एल० 12011/112/78-डी II ए दिनांक 2-7-80 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत भेजा है :

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur in terminating the services of S/Shri Mohan Dan; Chowkidar; Satyanarain Singh Clerk; Shyamlal, Clerk and Radheyshyam Gupta, Clerk with effect from 19-3-75, 10-6-72, 2-3-76 and 2-4-76 respectively is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. प्रबंधक, स्टेट बैंक ब्रीकानेर एण्ड जयपुर, जिसे प्रागे चलकर नियोजक सम्बोधित किया जाएगा ने राधेश्याम गुप्ता बलक, श्री मोहनदान चौकीदार, श्री सत्यनारायण क्लर्क एवं श्री श्याम लाल क्लर्क की सेवायें समाप्त कर दी। उनके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विवाद इस न्यायाधिकरण को भेजा गया है। इस मामले की सूचना संबंधित पक्षकारों को दी गई एवं यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि अब मामला श्री राधेश्याम गुप्ता बलक तक ही सीमित है क्योंकि अन्य कर्मचारियों को नियोजक ने पुनः सेवा में ले लिया है एवं उनके संबंध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। यहाँ यह भी अंकित करना आवश्यक है कि दिनांक 24-4-82 को नियोजक ने श्री राधेश्याम गुप्ता को अस्थायी नौकरी देने का प्रस्ताव न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु उक्त श्री गुप्ता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि जिस कालावधि में विवाद इस न्यायाधिकरण में लम्बित रहा श्री गुप्ता अन्य स्थान पर भली प्रकार नियोजित हो चुके थे। हमारे पूर्वाधिकारी ने दिनांक 24-4-82 को यह आदेश पारित किया कि विवाद अब केवल इस सीमा तक शेष रहता है कि जिस अवधि में श्री राधेश्याम गुप्ता बेरोजगार रहा उस अवधि का उसको वेतन अतिपूर्ति के रूप में दिया जाए अथवा नहीं। अतः हम अपने आपकी केवल उसी हद तक सीमित रखेंगे।

3. इसमें कोई विवाद नहीं कि श्री राधेश्याम गुप्ता ने बैंक में बलक की हसियत से दिनांक 28-8-73 से कार्य करना शुरू किया उन्होंने दिनांक 1-4-76 तक बैंक की विभिन्न शाखाओं में काम किया हालांकि वह कार्य लगातार नहीं किया। परन्तु दिनांक 1-4-76 को समाप्त होने वाले वर्ष में श्री गुप्ता ने 240 दिन से अधिक कार्य किया। श्री गुप्ता की सेवायें समाप्त करते समय धारा 25 एक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे प्रागे चलकर अधिनियम कहा जाएगा, की पालना नहीं की गई। दूसरे शब्दों में सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व उसे न तो एक माह का नोटिस दिया गया न ही उसकी एवज में एक माह का नोटिस वे धीरे नही अति पूरित सुभावशा। अतः जो आदेश दिनांक 1-4-76 को सेवा मुक्ती का श्री राधेश्याम गुप्ता के संबंध में पारित किया गया वह विधिगत नहीं है एवं उसे निरस्त किया जाता है।

69 GI/84—5

4. सामान्यतया धारा 25 एक अधिनियम की पालना न करने के कारण सेवा मुक्ति आदेश निरस्त किए जाने पर उस दिन की स्थिति पुनः स्थापित करनी पड़ती है अर्थात् उस श्रमिक को जिस के संबंध में सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है पुनः सेवा में लिए जाने के आदेश के साथ चढ़े हुए वेतन के पारित किया जाता है। इस मामले में जिस समय की सेवा मुक्ती का आदेश पारित किया गया श्री राधेश्याम गुप्ता अस्थायी लिपिक थे अतः वही स्थिति वह पुनः पाने के अधिकारी हो सकते थे। दिनांक 18-4-81 को जबकि अन्य श्रमिकों के संबंध में नियोजक की ओर से पुनः सेवा में लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। श्री राधेश्याम गुप्ता से भी संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था एवं यह कहा गया था कि नियोजक उन्हें पुनः अस्थायी लिपिक की हसियत से सेवा में लेने को तैयार है परन्तु श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दिनांक 22-8-79 को उन्होंने युनाइटेड इण्डिया इन्स्योरेन्स कंपनी में लिपिक की हसियत से स्थाई पद प्राप्त कर लिया था व नियोजक न केवल अस्थायी बलक का पद देने का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था श्री मनोज शर्मा विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चढ़े हुए वेतन का प्रश्न तभी उठ सकता है जबकि श्रमिक को धारा 25 एक अधिनियम की पालना न करने के कारण पुनः सेवा में लेने का आदेश पारित किया जाए। उसके अनुसार क्योंकि श्री राधेश्याम सेवा में भ्राना नहीं चाहते इसलिए उन्हें सेवा में लेने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता इस कारण चढ़े हुए वेतन का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु हम श्री शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हालांकि औद्योगिक विवादों का निपटारा शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिए परन्तु यह सर्वविदित है कि समझौता अधिकारी के समक्ष समय लगता है राज्य सरकार को भी विवाद निपटारे हेतु न्यायाधिकरण को भेजने में समय लगता है एवं न्यायाधिकरण में भी किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में काफी समय लगने की सम्भावना रहती है अतः श्रमिक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उस विवाद के निपटारे तक बेरोजगार रहे अतः इन परिस्थितियों में श्रमिक कहीं किसी अन्य नियोजक के अधीन सेवा प्राप्त कर लेता है तो उन विशिष्ट परिस्थितियों में श्रमिक को चढ़ा हुआ वेतन विलाए जाने का अधिकार न्यायाधिकरण को रहता है। इस संबंध में सुरेन्द्र कुमार वर्मा प्रादि बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल ट्रय्यूनल न्यू देहली, एफ० एल० धार० 1980 (वोल्सूम, 41) पेज 351 में व्यक्त किए गए उच्चतम न्यायालय के मत को विया जाना आवश्यक है, वह यह है :

"For instance, the industry might have closed down or might be in severe financial doldrums; the workmen concerned might have secured better or other employment elsewhere and so on. In such situations, there is a vestige of discretion left in the court to make appropriate consequential orders. The Court may deny the relief of reinstatement where reinstatement is impossible because the industry has closed down. The Court may deny the relief of award of full back wages where that would place an impossible burden on the employer. In such and other exceptional cases the Court may mould the relief, but, ordinarily the relief to be awarded must be reinstatement with full back wages. That relief must be awarded where no special impediment in the way of awarding the relief is clearly shown."

को शर्मा ने अपने तर्क में, कि रिस्टेटमेंट के आदेश के साथ ही चढ़ा हुआ वेतन विलाया जा सकता है, स्टेट बैंक बनाम एन० सुन्दर मनी, ए० आई० धार० 1976 (एस सी) पेज 1111 का सहारा लिया है।

5. इस मामले में श्रमिक की सेवायें दिनांक 1-6-76 के आदेश द्वारा समाप्त की गई थी और ऐसी धारा 25 एक अधिनियम की पालना बिना किया गया था। केन्द्र द्वारा विवाद इस न्यायाधिकरण को दिनांक 2-7-80 को प्रेषित किया गया। यह आशा नहीं की जा सकती थी कि राधेश्याम सम् 76 से सन् 80 तक इन्तजार में रहता या उसकी कोई अन्य पद प्राप्त हो उसको प्राप्त नहीं करता और उस आशा में बैठा रहता कि इस न्यायालय द्वारा विवाद निमित्त किए जाने पर वह पुनः सेवा में लिया जाएगा। अतः 22 अगस्त सन् 1979 को जब उसे स्थाई पद इन्स्योरेन्स कंपनी में प्रा

हुआ उसने वह पद प्राप्त कर लिया और उस पद से वह संतुष्ट है।  
 स्याई पद को छोड़कर स्याई पद, जिससे कि उसे सेवा में मुक्त किया गया पर आने का प्रश्न नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में 22 अगस्त मन् 79 तक श्री राधेश्याम गुप्ता वह वेतन पाने का अधिकारी है जो उन्को स्याई लिपिक के रूप में नियोजक के वहां प्राप्त होता था। पक्षकारों में विवाद नहीं कि दिनांक 2-5-76 से 21-8-79 तक श्री राधेश्याम गुप्ता ने विभिन्न नियोजकों के अधीन कार्य किया है, एवं जैसाकि उसके शपथ पत्र से सिद्ध किया है। उसने 13,483 रु 33 पैसे वेतन स्वरूप उस अवधि में प्राप्त किए थे। दिनांक 1-4-76 से दिनांक 21-8-79 का वेतन मिलना श्री राधेश्याम को मिलना चाहिए इसकी कोई सान्य उपलब्ध नहीं है अतः हम यह आदेश देते हैं कि दिनांक 1-4-76 से दिनांक 21-8-79 तक नियोजक श्री राधेश्याम गुप्ता को वह वेतन नियमानुसार अदा करें, जो कि श्री राधेश्याम गुप्ता सेवा मुक्ति के समय पा रहे थे। वेतन का निर्धारण उन वार्षिक वेतन वृद्धियों एवं डी.ए.आर. की जोड़कर किया जाएगा, जो कि नियमानुसार समय समय पर देय होते। उक्त वेतन से से 13,483 रु 33 पैसे जो श्री राधेश्याम गुप्ता ने वेतन के अन्य नियोजक के अधीन कार्य करके प्राप्त किए हैं। नियोजक काटने का अधिकारी होगा एवं वह वेतन अदा करेगा श्री गुप्ता और कोई राशि पाने के अधिकारी नहीं हैं। विधीयत अर्थात् पविलन होने के 15 दिन में नियोजक यह राशि अदा करे अन्यथा नगण्यता बड़ी रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भुगतानी कर श्री राधेश्याम गुप्ता को नियोजक अदा करें। इस प्रकार का अर्थात् पारित किया जाता है। यह अर्थात् केन्द्र सरकार को वास्ते प्रकाशनाथ भेजा जावे।

महेंद्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश  
 [मं० एल०-12011/11/ड०-II(ए)]

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 1397.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of India, Pune and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY, CAMP : NAGPUR

Reference No. CGIT-2/41 of 1983

Employers in relation to the management of Bank of India, Pune

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. M. Bhendarkar, Industrial Relations Officer.

For the workmen—Shri S.T. Shastrabudhe, Dy. General Secretary, V.B.E.F.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Nagpur, the 22nd March, 1984

AWARD

(Dictated in the open Court)

By their Order No. L-12012(77)/83-D.II dated 17-11-1983 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Bank of India in refusing to take into account the period of temporary employment of four months two days from 12-1-75 to 13-4-1976 as part of Probationary period of Shri S. B. Bhendarkar, Agricultural Clerk, Hingan-

ghat Branch is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The facts as appearing on the record shortly stated are that the concerned workman Shri S. B. Bhendarkar served during certain spells of periods as a temporary Agricultural Clerk, Hinganghat Branch of Bank of India. The spells were from 12-11-1975 to 10-1-1976, 19-1-1976 to 18-3-1976 and lastly from 10-4-1976 to 13-4-1976. Later on he was appointed as a Probationer on 17-4-1976 and ultimately he was confirmed on 17-10-1976. Now the contention of the workman is that the earlier period of his temporary appointment by virtue of Para 20.8 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 is to be included so as to give effect from the back date. It is his contention that since his appointment was in a permanent vacancy and since he was eventually selected the period of such temporary employment is to be treated as part of his probationary period. As a result if his request is granted his date of appointment would be with retrospective effect from 12-11-1975 on which date he was initially appointed with all consequential benefits.

3. The Bank has come out with a denial saying that the workman was initially appointed on 17-4-1976 in a permanent vacancy therefore reliance on para 20.8 of the Bipartite Settlement is futile as such his claim must fail.

4. On the strength of the above pleadings the following issues arise for consideration and my findings are :—

ISSUES

FINDINGS

1. Whether the case of the concerned workman is governed by the para 20.8 of the Bipartite Settlement? No
2. If not, is the earlier period of temporary employment to be treated as part of probationary period? No
3. Was the Bank justified in not treating the same as probationary period? Yes
4. To what relief the workman is entitled? As per award.

REASONS

5. It is a fact not in dispute that there are three categories of employees in the Bank namely temporary employees, probationary and permanent employees. The fact that prior to 17-4-1976 the workman was a temporary employee cannot be gain-said although at the time of argument it was argued that because the workman was then working in an existing post he should be deemed to be a permanent employee. Even the order of reference which gives me jurisdiction to adjudicate the dispute speaks "whether the action of the management of Bank of India in refusing to take into account the period of temporary employment of four months two days". The fact therefore that the employment before his appointment as probationer on 17-4-1976 was a temporary employment at least cannot be now disputed in view of the order of reference itself.

6. Consequently what shall have to be determined is whether Para 20.8 of the Bipartite Settlement is at all attracted. Now under the said paragraph what is necessary is that there should be a temporary workman, he should be appointed to fill in a permanent vacancy, that such appointment shall not exceed three months during which period the Bank is enjoined to make suitable arrangement and lastly such temporary workman who is appointed to fill in the permanent vacancy must be eventually selected for filling up the vacancy. Unless all these considerations or qualifications are fulfilled no period of temporary service will be considered as part of probationary period. Naturally what is crucial for determination of the present dispute is whether the appointment of Shri Bhendarkar prior to 17-4-1976 during the three spells in question was in a permanent vacancy? If there is proof of permanent vacancy the workman must get the benefit but not otherwise. As already stated whether there was a permanent vacancy or not is distinct from the question whether there was work or not. The existence of work may justify creation of post but from such existence we cannot come to the conclusion immediately that the permanent post must be subsisting to which the workman was appointed. Argument therefore drawing attention or pointing out to the recommendations of the Branch Manager to substantiate his demand for

creation of additional post would be of no avail. The record speaks that the permanent vacancy in fact was created on 29-6-1977 whereby additional staff was sanctioned by the Bank.

7. Now relying upon the appointment as probationer on 17-4-1976 it was tried to be urged that the very fact probationary appointment was made earlier than 29-6-77 indicate that the post must be there. As already indicated it is not the necessity of post but existence of post which is material for the purpose of application of Para 20.8 of the Bipartite Settlement and as record goes the proof of existence of vacancy prior to 29-6-1977 is lacking in the present case. Bank can appoint a probationer any time but when any inference has to be drawn in the absence of order, there must be proof.

8. The Bank has explained as to how before the creation of the permanent vacancy there was an appointment of Shri Bhendarkar. It seems that initially there was an advertisement dated 10-8-1973 in pursuance of Annexure I to the list dated 21-3-1984. The Bank must have interviewed the incumbents and it is stated that waiting list was prepared. The name of Shri Bhendarkar was in the said waiting list. Now I am further given to understand that in case the waiting list is not exhausted for one reason or other before the succeeding advertisement then the waiting list lapse as a result of which the candidates are likely to suffer. It may happen that a candidate though selected and therefore kept on the waiting list, on the next occasion may not be selected for one reason or other and it may result in permanent loss of opportunity. At annexure III dated 30-3-1976 of list dated 21-3-1984 this fact has been specifically stated and it further shows the subsequent intention of the Bank, why to have a fresh advertisement. Consequently in order to help Shri Bhendarkar or similarly placed candidates if the Bank appointed him as Probationer on 17-4-1976, it does not mean that permanent vacancy existed nor from the definition of Probationer we can jump to such a conclusion. After all it is clear from the record that the creation of vacancy was on 29-6-1977. Therefore atleast upto 13-4-1976 even if Shri Bhendarkar had worked at Hinganghat Branch, we cannot conclude his appointment must be in a permanent vacancy and unless I come to such a conclusion para 20.8 can never be attracted.

9. Another question in view of wording of para 20.8 is as to whether the workman can claim benefit of more than three months. The paragraph enjoins on the management to make arrangement for filling up the vacancy permanently within three months. Of course in the instant case I need not consider the same since there is no proof of a permanent vacancy. Another question posing for determination is whether selection must be for the very vacancy or can be in any vacancy. Here again I need not delve in view of the non-existence of permanent vacancy before the date of appointment as probationary on 17-4-1976. In my view for all these reasons para 20.8 of the Bipartite Settlement is not at all attracted, the question of considering the earlier period does not arise and as such no relief is permissible.

Award accordingly. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[L-12012/77/83-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

S.O. 1398.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th April, 1984.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण

केस नं० सी० आई० टी० 2/1982

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० नं० 12012/220/80  
डी० II (ए) दिनांक 19-12-81

मैक्रोटी, राजस्थान बैंक एम्प्लॉईज यूनियन, रामपुरा बाजार कोटा ।

..... प्रार्थी

प्रसिस्टेंट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, हिबो जनन आफीस,  
बनी पार्क जयपुर ।

..... अप्रार्थी

उपस्थिति

संघ की ओर से : कोई हाजिर नहीं है  
नियोजक की ओर से : एम० बी० माथुर  
दिनांक अवार्ड : 7-3-83  
अवार्ड

केन्द्र सरकार निम्नलिखित विवाद इस न्यायधिकरण को बास्ते निपटारा  
अपनी अधिसूचना सं० 12012/220/80-डी II (ए) दिनांक 19-12-81  
के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1)  
के अन्तर्गत भेजा है ।

"Whether the action of the management of United Commercial Bank in relation to its Kota Branch in imposing the penalty of stoppage of one increment of Shri Nahar Singh Rathore, Sub-staff from 22-5-80 is justified. If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

श्री एम० बी० माथुर बिपक्षी बैंक की ओर से उपस्थित हैं । तामील के पश्चात् प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई हाजिर नहीं है । यूनियन को नोटिस दिनांक 2-2-83 की पेची का तामील हो चुका है किन्तु उनकी ओर से आज तक कोई क्लेम पेन ही किया गया है यूनियन की क्लेम के लिए दिनांक 25-9-82 से समय दिया जा रहा है । किन्तु कोई क्लेम पेन नहीं किया गया है इससे जाहिर है कि यूनियन इस मामले को चलाने में कोई दिव्यरूपी नहीं रखती है । अतः यूनियन द्वारा क्लेम पेन नहीं करने से इस मामले में नो डिस्पूट अवार्ड पास किया जाता है जो भारत सरकार को बास्ते प्रकाशन भेजा जावे मुकदमा शुमार फैसल हो ।

महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश

[सं० एल० 12012/220/80-डी-II-(ए)]

एल० के० बनी, बैंक आफिसर

अवधि

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का० ग्रा० 1399.—केन्द्रीय सरकार की राय की है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैमर्स सिगरेटी कोमियरीज क० लि०, कोटा मुडियम (ग्र० प्र०) के प्रबंधन में सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिसका मुख्यालय है दराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

"क्या मैमर्स सिगरेटी कोमियरीज क० लि०, कोटा मुडियम के प्रबंधन की अपने कार्यालय आदेश दिनांक 7/4-4-1983 के द्वारा श्री मोहम्मद याकूब अली को रमायतन के पद से उमके स्थाई पद जनरल मैजिस्टर (क्वें-2) पर पदावनत करने की कार्यवाही न्यायोचित है यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?"

[सं० एल० 22011/46/83 डी०-3 (बी)]

New Delhi, the 23rd March, 1984

## ORDER

S.O. 1399.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Kothag Gudium (A.P.) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium are justified in re-verting Shri Mohd. Yacoob Ali from the post of Chemist to his substantive post of General Mazdoor (category II) vide their Officer Order dated 7/9-4-1983? If not to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-22012/40/83-D.III(B)]

## भावना

का० प्रा० 1400:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जिल्लिंग लंगालोटा धातुखान और माईन्स प्राफ मैसर्स एस० लाल एण्ड कं० लि०, डाकघर बारबिल के प्रबंधन से सम्बन्धित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (I) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० जे० एम० मोहपात्रा होंगे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

## अनुसूची

“क्या जिल्लिंग लंगालोटा माईन्स प्राफ मैसर्स एस० लाल एण्ड कं० लि०, डाकघर बारबिल, जिला ब्योहार के प्रबंधन की धातुखान और माईन्स प्राफ मैसर्स एस० लाल एण्ड कं० लि०, डाकघर बारबिल की 7-7-83 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?”

[सं० एल०-26012/25/83-डी० 3 (बी)]

## ORDER

S.O. 1400.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jilling Langelota Iron Ore Mines of M/s. S. Lal & Co. Ltd., Post Office Barbil and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mohapatra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

“Whether the action of the management of Jilling Langelota Mine of Messrs S. Lal & Co. Ltd, Post Office Barbil, District Keonjhar in dismissing from service Shri Sudama Singh, Operator/Driver with effect from 7-7-83 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

[No L-26012/25/83-D.III(B)]

## भावना

नई दिल्ली, 28 मार्च 1984

का० प्रा० 1401:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, रामकृष्णपुर डिवीजन 2, डाकघर रामकृष्णपुर, जिला प्रदिलाबाद प्रबंधन से सम्बन्धित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा (I) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

## अनुसूची

“क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, रामकृष्णपुर डिवीजन 2 डाकघर रामकृष्णपुर जिला प्रदिलाबाद (प्रा० प्रा०) का प्रबंधन से सम्बन्धित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है?”

(क) सर्वश्री (1) जो० मल्ला रेड्डी, (2) पी हनुमैया, (3) सुकरी रायामल्लु, (4) बी० बेंटेश्वर राव और (5) नल्ला राजा रेड्डी को 1-5-1981 से हालर खलासी के रूप में बर्ग 4;

(ख) सर्वश्री (1) कोठा मल्ला रेड्डी, (2) योगी नीलेया, (3) मल्ला बीजीमल्ल, (4) बी० सुन्दर, (5) मल्ला पेशाम, और (6) डावर को 4-8-1981 से पम्प खलासी के रूप में बर्ग-3; और

(ग) सर्वश्री (1) पोन्नाला पोशाम, (2) एड्डू राजीव, (3) दयम पोशाम, (4) पेन्टा राजैया, (5) पेन्नाला राजम, (6) टोरेटी किलैया, (7) बाबलू शंकर (8) बजी राजम, और (9) मैकाला रायशिंगू को 4-8-1981 से ड्रिलर के रूप में बर्ग-5; देने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल० 22011/55/83-डी०-3(बी)]

## ORDER

New Delhi, the 28th March, 1984

S.O. 1401.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Co., Ltd., Ramakrishna Pur Division-II, P. O. Ramakrishna Pur Distt. Adilabad (A.P.) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

Whether the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Ramakrishnapur Division, II, P. O. Ramakrishnapur, Distt. Adilabad (A.P.) are justified in denying :—

- (a) Category IV as Hauler Khalasis with effect from 1-5-1981 to S/Shri (1) G. Malla Reddy, (2) P. Hanumaiah, (3) Sunkari Rayamallu, (4) B. Venkateshwara Rao and (5) Nalla Raja Reddy;
- (b) Category III as Pump Khalasis with effect from 4-8-1981 to S/Shri (1) Kotha Malla Reddy, (2) Bogi Neelalah, (3) Algu Buchimallu, (4) V. Surendar, (5) Sirimalla Posham and (6) Md. Khadar; and
- (c) Category V as Drillers with effect from 4-8-1981 to S/Shri (1) Ponnala Posham, (2) Eddu Rajeev, (3) Katham Posham, (4) Penta Rajaiah, (5) Peddala Rajm, (6) Todety Kishtiaiah, (7) Bathula Shankar, (8) Buchi Rajam and (9) Mekala Rayalingu;

all workman of R.K.8. Incline ? If not to what relief are the workmen concerned entitled ?

[No. L-22011/55/83-D.-III(B)]

## आदेश

कां.प्र. 1402.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स एस० लाल एण्ड कं० लि०, कासिया लोह भयस्क खान मालिक, झाकबर बाराबिल (उड़ीसा) के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्बंधित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा (I) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे०एम० मोहपात्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्बंधित करती है।

## अनुसूची

"मैसर्स एस० लाल एण्ड कं० लि०, की कासिया लोह भयस्क खान से मालिक हैं, के प्रबंधन की कोकियादर, बी वेब थोहली की 15-5-83

से संबंधित करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?"

[सं० एल-26012/28/83-बी-3 (बी)]

नन्द लाल, प्रवर सचिव

## ORDER

S.O. 1402.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs S. Lal & Co. Ltd., Owner of Kasia Iron ore Mines, P. O. Barbil (Orissa) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mohapatra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs S. Lal and Company Ltd., Owner of Kasia Iron Ore Mines in dismissing from service Sh. Baida Mehanto, Watchman, with effect from 15-5-83 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

[No. L-26012/26/83-D-II(B)]

NAND LAL, Under Secy.

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 1403.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khetri Copper Complex Mines and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th April, 1984.

## केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 13/82

केन्द्र सरकार भ्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एल-47012/4/81

डी० III-बी० दिनांक 26-2-82

जनरल सैक्रेटरी, खेतड़ी कानपुर मजदूर संघ

खेतड़ी नगर।

प्रार्थी

## बनाम

जनरल मैनेजर, खेतड़ी कोपर कोपलेक्स, हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, पोस्ट ग्राम खेतड़ी नगर, जिला मुम्बई।

प्रार्थी

उपस्थिति

संघ की ओर से :

कोई हाजिर नहीं है

नियोजक की ओर से :

श्री मनोज शर्मा

दिनांक प्रकाश :

3-3-83

## प्रवाद

केन्द्र सरकार निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते निवेदित अपनी अधिसूचना सं० 43012/4/81-बी-III की दिनांक 26-2-82 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत सेवा है :

"Whether the action of the management of M/s. Khetri Copper Project in promotion of Shri Bhawani Singh and Bala Ram as Senior Fitter in 1974 and ignoring the claim of Shri Gaur Dayal, Fitter 'A' who was Senior to them was justified. If not to what relief is the workmen entitled."

श्री मनोज शर्मा कम्पनी की ओर से उपस्थित हैं। प्रार्थी युनियन की ओर से कोई हाजिर नहीं है। तामिल होने की रसोई प्राप्त हो चुकी है कोई क्लेम पेश नहीं किया गया है अतः क्लेम पेश नहीं करने से इस मामले में नो डिस्पूट अवार्ड पास किया जाता है जो भारत सरकार की वास्ते प्रकाशन प्रस्तुत किया जावे।

[सं० एल० 43012/4/81-D-III (B)]

महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश  
नन्दलाल, अवर सचिव

S.O. 1404.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bundi Silica Sand Supply Company P.O. Kunadi, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th April, 1984.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, JAIPUR

Case No. C.I.T. 1/1981

#### REFERENCE :

Under Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi Order No. L-29011/39/80-D. III(B) dated 26th December, 1983.

In the matter of an Industrial Dispute

#### BETWEEN

Silica Sand Khan Mazdoor Union, Bundi

#### AND

M/s. Bundi Silica Sand Supply Company P.O. Kunadi, Rajasthan.

#### PRESENT :

For the Applicant Union—Shri. M. F. Beg.  
For the Opposite Party : .

Date of Award : 19th August, 1983

#### AWARD

The dispute is with regard to certain demands of workmen of M/s. Bundi Silica Sand Supply Company, P.O. Kunadi (hereinafter referred as Company). The demands which have been referred by the Central Government are as follows :—

- (1) Whether the demand of Silica Sand Khan Mazdoor Union for payment of Rs. 250 as a monthly wage to the workers employed in the Bundi Silica Sand Supply Company is justified? If not, to what relief the workers are entitled?
- (2) Whether the demand made by the Silica Sand Khan Mazdoor Union, Bundi for making payment of Rs. 300 as grain advance to those workers who are regularly contributing to Provident Fund is justified? If not, to what relief the workers are entitled?
- (3) Whether the demand of the Silica Sand Khan Mazdoor Union for granting 10 paid national holidays to the workers namely Republic Day, Holi, Independence Day, Rakshabandhan, Janmashtmi, Mahatma Gandhi Jayanti, Dussahara, Deepawali, Shivratri and Teej every year is justified? If not, to what relief the workers are entitled?

2. The union has filed the statement of claim in which a case has been set up that looking to the increase in dearness, a demand was raised that the basic wages of a worker should be Rs. 250 per month but the same was not met. It is also the case that the workers of Rajasthan State Mines and Mineral development are paid Rs. 500 p.m. as wages besides other facilities such as dearness allowance etc. Apart from that on increase of every point Rs. 1.30 paise is paid extra. Hindustan Zinc is also an undertaking of the Central Government and the workers working on the Mines are paid Rs. 650 p.m. It is also the case of the union that on an average a worker produces material worth Rs. 1,000 and is only paid Rs. 7 per day. The union has also made two more demands for payment of Rs. 300 as advance for purchase of food-grains and for 10 days paid holidays.

3. The company in its reply to the statement of claim has set up a case that earlier Rs. 6 per day was paid to each of the worker but under the settlement dated September 2nd 1980 w.e.f. November 8th 1980 each of the worker is being paid @ Rs. 7 per day. According to the company these wages are more than the output of a worker. It is also the case that no wages can be fixed for the workers so far as the Mines are concerned, and this Tribunal cannot fix the wages. So far as the demand of the workers for 10 paid holidays is concerned, the opposite party in para 3 of its reply has come out with a case that 9 paid holidays are being given. If the workers so like the company is willing to declare Teej or Shivratri as a paid holiday in place of Hariyali Amavas.

4. In support of the case on behalf of the union affidavits of Servshri Veersingh, Ramlal and Kodar have been produced. They were cross examined on their affidavits by the learned counsel of the company. On behalf of the company affidavits of Sarvshri Satya Narayan Sharma, Krishan Gopal and Ajay Pal were produced and opportunity was granted to Shri Beig to cross examine them but Shri Beig only examined Shri Ajay Pal and did not examine other deponents.

5. The parties have also placed reliance on documentary evidence which shall be referred as and when necessary.

6. I have heard the learned counsel for the parties and have perused the available material. I will take three demands which have been reproduced in the earlier part of the Award one by one.

#### Demand No. 1 :

7. As per the case of the company each of the worker is paid Rs. 7 per day. The demand of the union is that the worker should be paid basic wages amounting to Rs. 250 p.m. Shri Veersingh in his affidavit has stated that prior to November '81 Rs. 7 per day were paid as wages to each of the worker but from November '81 the wages were increased to Rs. 8 per day and from December 9th Rs. 8.60 paise per day. Besides these wages no other facilities are provided to the workers. According to him each worker loads about 160 tagaries of mineral (silica sand) in case I is output is less than that his wages are deducted. He also states that about 18 kg. of silica sand is carried in one tagari. The value of the material which is loaded by each of the worker is Rs. 273.60 paise. In cross examination he states that silica sand is quarried with the help of Genti. Thereafter it is filled in the tagari with the help of spade and form there taken to a distance and unloaded there. Only then one token is given. Other deponents Shri Ram Lal has corroborated his statement. He is the General Secretary of the union. According to him the gaps of the Mine is about 60 to 70 feet. He pleaded ignorance about the existence of any certified standing orders of the company. Shri Kodar, the last of the three deponents produced on behalf of the union has also corroborated the other witnesses. He states that they should be paid Rs. 250 and other wages.

8. The company in the three statements produced on its behalf has denied that the workers are entitled to this demand. According to Shri S. N. Sharma a settlement was arrived at on December 2nd 1980 under which norms of work were fixed. He also states that 9 paid holidays are given to the workers as per the certified standing orders. Shri Kishan Gopal has stated that besides doing the regular work, extra work is also done and the workers earn about Rs. 350 p.m.

Shri Ajay Pal has also corroborated them and states that wages are paid for holidays Holi and Deepawali. A settlement has been produced on behalf of the company, copies of which do not appear to have been sent to the Labour Officer as required by law. The norms of work were fixed under the settlement.

9. From the above evidence it appears that though the wages @ Rs. 7 per day were being paid to the workers when the dispute was referred for adjudication to this Tribunal, but when the dispute was pending here, the wages have been increased to Rs. 8.60 per day. If the monthly wages are considered taking the daily wages @Rs. 8.60 per day, the wages of each of the worker will be more than Rs. 250 per month, if a worker works for 30 days in a month. But the submission of Mr. Beig learned counsel for the union is that when a worker is paid daily wages, he is paid only for 26 days in a month. In other words he is not paid for 4 days i.e. for sundays falling in a month. He, therefore, submits that if the wages @ 8.60 per day are calculated for 26 days, they will be less than Rs. 250 p.m. Looking to the nature of the duties which a worker has to discharge i.e. he has to load at least 160 Tagaries each weighing about 18 kg., it can be said that the wages at Rs. 8.60 per day, may be minimum wages for the workers working in mines, but are not the fair wages. According to him the fair wages will be atleast Rs. 250 per month and looking to the financial position of the company if the wages are fixed at Rs. 250 per month, they will not be excessive. As per the affidavits produced on behalf of the union, in Rajasthan State Mines and Mineral Development and Hindusthan Zinc an undertaking of the union of India, the workers working in the Mines are paid at Rs. 560 per month. No evidence has been led as to what are the wages and their mode of payment whether daily or monthly in other silica mines in Rajasthan.

10. In present day escalation of price and the ever increasing cost of living index, the demand of the workers that they should be paid at the rate of Rs. 250 per month looking to the nature of work and the minimum needs of the worker as well as the financial position of the company, it can not be said to be unreasonable. The demand of Rs. 250 per month as wages appears to be justified.

11. I, therefore, hold that each of the worker of the company is entitled to Rs. 250 per month as wages from the date of the publication of this Award. The workers should be entitled to these wages, if he works on all working days in a month.

Demand No. 2 :

12. This demand about advance for foodgrains of Rs. 300 does not appears to be justified.

Demand No. 3 :

13. It has come in the evidence that there are certified standing orders and under the certified standing orders 9 paid holidays are granted to the workers. The case of the union is that it was not knowing about the existence of certified standing orders and the holidays specified therein were not being given to the workers. Be that as it may, as the company admits that 9 paid holidays, (festival and national) are to be given under the certified standing orders, it is hereby ordered that each of the worker shall be entitled to the paid holidays in accordance with the certified standing orders.

14. Let this Award be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1983.

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer

[No. L-29011/39/80-D.III (B)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1984

का.आ. 1405—केन्द्रीय सरकार, अधक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 3 तथा 19 के साथ पठित अधक खान श्रम

कल्याण निधि अधिनियम, 1946 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (ii), दिनांक 15 अगस्त, 1981 के पृष्ठ 2603 पर का.आ संख्या 2198 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2 तथा 10 में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"2. कल्याण आयुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन  
भारत सरकार,  
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय  
(श्रम विभाग),  
कर्मा, डाकघर भुमरितैया,  
जिला हजारीबाग बिहार-- उपाध्यक्ष"  
(पदेन)

"10. कल्याण प्रशासक,  
अधक खान श्रम कल्याण संगठन  
कर्मा, डाकघर भुमरितैया,  
जिला हजारीबाग, बिहार - सचिव"  
(पदेन)

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"2 केन्द्रीय सरकार, अधक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 19(1) के अनुसरण में कर्मा को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है।"

[का.सं.यू-18017/1/82-एम० III/उपल्यू-II]

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 1405.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 read with rule 3 and 19 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby amends the notification published vide S.O. No. 2198 in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 15th August, 1981 at page 2603 as under :—

In the said notification, at serial number 2 and 10, the following shall be substituted, namely :—

"2. Welfare Commissioner,  
Labour Welfare Organisation,  
Government of India,  
Ministry of Labour & Rehabilitation  
(Department of Labour),  
Karma, P.O. Jhumritelaiya,  
District Hazaribagh, Bihar" ...Vice Chairman

"10. Welfare Administrator,  
Mica Mines Labour Welfare Organisation,  
Karma, P.O. Jhumritelaiya,  
District Hazaribagh, Bihar" ...Secretary (Ex-officio)

In the said notification, the following shall be added at para 2, namely :

"2. In pursuance of rule 19(1) of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby fixes Karma to be the head-quarter of the said Advisory Committee."

[F. No. U-18017/1/82-M.III/W.II]

का.आ. 1406—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 तथा नियम 16 के उप-नियम (ii) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) दिनांक 5-12-1981 में का.आ.सं. 3328 द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-यू० 23018/1/81-उच्चय II, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2, 7 तथा 9 के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. कल्याण आयुक्त,  
अजुमन बिल्डिंग, पहली मंजिल,  
रेजिडेंसी रोड, सदर,  
नागपुर।

—अपाध्यक्ष

"7. श्री एम.एन. रामटेक,  
महा सचिव,  
महाराष्ट्र बीडी मजदूर संघ,  
काम्पटी, नागपुर।

—कर्मचारियों के प्रतिनिधि

"9. श्रीमती राधाबाई काम्बले,  
उपाध्यक्ष,  
शोलापुर बीडी कामगार यूनियन (एटक), —महिला प्रतिनिधि  
505, साखर पेथ शोलापुर।

[फा० सं० यू-23018/1/81-एम० V/उच्चय II]

S.O. 1406.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (Act 62 of 1976) read with sub-rule (ii) of Rule 3 and rule 16 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby makes the following amendments in notification No. U-23018/1/81-W.II dated the 19th November, 1981 of the Government of India in the Ministry of Labour published at pages 3800 to 3801 of the Gazette of India, Part II Section 3(ii) dated 5-12-1981 vide S.O. No. 3328 namelyq :—

In the said notification for the entries against serial number 2, 7 and 9, the following shall be substituted namely :—

"2. Welfare Commissioner,  
Anjuman Building, 1st floor,  
Residency Road, Sadar, Nagpur.

...Vice-Chairman

"7. Shri. S. M. Ramtke,  
General Secretary,  
Maharashtra Bidi Mazdoor Sangh,  
Kamptee, Nagpur. ...Employees' representative.

"9. Smt. Radhabai Kamble,  
Vice President,  
Sholapur Bidi Kamgar Union  
(ATTUC), 505, Sakhar Peth,  
Solapur. ...Woman representative

[File No. U-23018/1/81-MV/W.II]

का० धा० 1407—केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3, अप खंड (ii), दिनांक 13 मार्च, 1982 के पृष्ठ 1168-69 पर का० धा० संख्या 1149 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्न लिखित संशोधित करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के पैरा 1 तथा पैरा 2 में निम्नलिखित रखा जाएगा :—अर्थात् :

पैरा-1

2. कल्याण आयुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,

भारत सरकार,  
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,  
(श्रम विभाग)  
कर्मा, डाकघर जूमरितिलैया,  
जिला हजारीबाग, बिहार — उपाध्यक्ष (पदेन)

पैरा-2

"कल्याण प्रशासक,  
चूना पत्थर और डोलोमाइट खान  
श्रम कल्याण संगठन, कर्मा,  
डाकघर जूमरितिलैया,  
जिला हजारीबाग, बिहार उक्त सलाहकार  
समिति के सचिव होंगे।"

[संख्या यू-23018/14/80-एम.V(उच्चय II)]

S.O. 1407.—In exercise of powers conferred by section 7 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) read with rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby amends the notification published vide S.O. number 1149 at pages 1168-69 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 13th March, 1982, namely :—

In the said notification at serial No. 2 of para 1 and para 2, the following shall be substituted, namely :—

Para 1

2. Welfare Commissioner,  
Labour Welfare Organisation,  
Government of India,  
Ministry of Labour and Rehabilitation  
(Department of Labour)  
Karma, P.O. Jhumritiliaya,  
District Hazaribagh, Bihar ...Vice Chairman

Para 2

Welfare Administrator,  
Limestone and Dolomite Mines Labour  
Welfare Fund Organisation, Karma  
P.O. Jhumritiliaya District  
Hazaribagh, Bihar shall be the Secretary of the said  
Advisory Committee.

[No. U-23018/14/80-M.V/W.II]

का० आ० 1408—केन्द्रीय सरकार, लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 तथा 16 के साथ पठित लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 20 फरवरी, 1983 में का० आ० संख्या 717 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 के क्रमांक 2 और 10 तथा पैरा 2 के सामने की गई प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

पैरा 1

"2 कल्याण आयुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,  
अजुमन बिल्डिंग (पहली मंजिल),  
रेजिडेंसी रोड, सदर  
नागपुर"

—उपाध्यक्ष (पदेन)



"10 कल्याण प्रशासक,  
श्रम कल्याण संगठन,  
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,  
नागपुर"

—सचिव

पैरा-2 "लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान  
श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 16 के अनुसरण में  
केन्द्रीय सरकार नागपुर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय  
नियत करती है।"

[संख्यायू. 23017/7/80-एम-IV (बल्यू-II)]

कंवर राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

S.O. 1408.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rules 3 and 16 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby amends the notification dated the 2nd February, 1982 published vide S.N. No. 717 at page 728 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th February, 1982 as under :—

In the said notification, entries against serial numbers 2 and 10 of para 1 and para 2, the following shall be substituted namely :—

Para 1 :

"2. Welfare Commissioner,  
Labour Welfare Organisation,  
Ministry of Labour, Govt. of India,  
Anjuman Building, 1st Floor,  
Residency Road, Sadar, Nagpur.

...Vice-Chairman

"10. Welfare Administrator,  
Labour Welfare Organisation,  
Ministry of Labour, Govt of India,  
Nagpur.

...Secretary

Para 2 :

"In pursuance of rule 16 of the Iron Ore Mines Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government fixes Nagpur to be the headquarter of the said Committee.

[No. U-23017/7/80-M.IV/W.III]

KANWAR RAJINDER SINGH, Under-Secy.

भारदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1984

कां.मां. 1409—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावय्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन संक्रियाएं), भारतीय खाद्य निगम, मद्रास-600001 के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध एक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947-का 14) की धारा 7-क और 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी. प्रवलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

69 GI/84—6

अनुसूची

"क्या संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन संक्रियाएं) भारतीय खाद्य निगम, मद्रास-600001 की लोडिंग मजदूर श्री के. धीरू बैगाडम, की 12-6-86 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-2012/1/83-डी-4 (बी)]

एस० एस० मेहता डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1984

S.O. 1409.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Joint Manager (Port Operations), Food Corporation of India, Madras-600001 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Joint Manager (Port Operations), Food Corporation of India, Madras-600001 in terminating the services of Shri K. Thiruvengadam, Loading Mazdoor, with effect from 12-6-82, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-42012(1)/83-D.IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 17th April, 1984

S.O. 1410.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Telegraph Office, Kanpur and their workman, which was received by the Central Government on the 29th March, 84.

BEFORE SHRI O.P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW  
DELHI

I.D. No. 112/80

In the matter of dispute between

Sh. Rattan, son of Shri Brij Lal, r/o Qr. No. 15/297  
Emergency Ward Compound, U.H.M. Hospital,  
Parade, Kanpur-208001.

VERSUS

The Union of India, through the Superintendent In-charge, Central Telegraph Office, The Mall, Kanpur-208001.

APPEARANCE:

Shri Narendra Chaudhary for the Central Telegraph  
Office,

Shri A.P. Anand for the workman.

## AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L.40012 12 5 79-13 II. B. dated 10th October, 1980, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the Superintendent In-charge, Central Telegraph Office, Kanpur's action in terminating the services of Shri Rattan, Farash, from 30-6-78 is fair, just and legal? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Shri Girja Shanker, Farash was recruited for appointment and was posted as a Chowkidar and in his place the workman Mr. Rattan was appointed as a Farash. He worked as officiating Farash from 8-1-77 to 30-6-78 on the pay scale 196-232 plus usual allowances. His services were terminated vide letter No. E4/8 dated 28-6-78 by Superintendent In-charge, Central Telegraph Office, Kanpur w.e.f. the afternoon of 30-6-78. The workman complying with section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 and that several Junior employees like Sri Kamla Kant Bajpai, Ravindra, Smt Suresh Kumari and Smt. Durga Devi have been retained in service; even though they joined later. The workman claimed reinstatement with full back wages and continuous service.

3. The Management contested the claim. It was pleaded that the dispute was not one which attracted section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 because the petitioner-claimant was governed by C.C.S. (Temporary Service) Rules 1964 and this Tribunal had no jurisdiction.

4. On facts, it was pleaded that the appointment of Farash was casual and was not continuous and that his services were no longer required and were properly terminated. Kamal Kant had not worked as Farash. He stood first in the merit list of casual labours and was Senior to Rattan. Rattan's service were terminated due to abolition of post being posted as Water man and Farash. The claimant could not claim benefit under section 25-F of I.D. Act or Rule 5 of C.C.S. (Temporary Service) Rules.

5. The workman's statement by way of affidavit has been accepted and he has been cross-examined. The Management filed the affidavit of A. Chinnakkani, Superintendent Central Telegraph Office, Kanpur and he has been cross-examined by the workman's representative. I have heard the representative of the parties.

6. The claimant Rattan did work for more than 240 days during the period 8-1-77 to 30-6-78 and ostensibly claims the benefit of protection of section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947.

7. There is a recent judgment of Patna High Court Full Bench in case B. K. Bharti v State of Bihar and Others (1983 Lab. I.C. 1884) where the applicability of section 25-F I.D. Act, 1947, Government Department is examined. It reads as under:—

"If there are enactments, or rules framed under Art. 309 of the Constitution, which either expressly or by necessary implication exclude the operation of the Industrial Disputes Act, no question of applicability of the provisions of the Act arise. The mere fact that there is a Service Code dealing with some of the aspects of the employer-employee relationship between the Government and its Employees does not amount by necessary implication to the exclusion of the provision of the Act to Government Departments. If there were rules, for instance, specifically dealing with the manner in which temporary appointments could be terminated, it could legitimately be argued that S. 25F of the Act is excluded. For then, the rules framed under the constitutional provisions would have precedence over the provisions of the Act. It is not possible to accept the extreme contention that the provisions of the Industrial Disputes Act do not at all apply to Government servants".

8. The appointment of Rattan was not as a Daily-paid worker but on a regular scale and he must be accepted as a temporary servant under C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965 and section 5 of these rules applied to him and these rules are made under Article 309 of the Constitution of India and they eliminate the applicability of section 25F I.D. Act, 1947.

9. Section 5 of the C.C.S. (Temporary Service) Rules is in the following terms on account of the amendment made in 1972.

- "5. (1) (a) The services of a temporary Government Servant who is not quasi-permanent service shall be liable to termination at any time by a notice in writing given either by the Government servant to the appointing authority or by the appointing authority to the Government servant;
- (b) the period of such notice shall be one month; Provided that the service of any such Government servant may be terminated forthwith (and on such termination the Government servant shall be entitled to claim) a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his services, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

Note:—The following procedure shall be adopted by the appointing authority while serving notice on such Government servant under clause (a) :—

- (i) The notice shall be delivered or tendered to the Government servant in person;
- (ii) Where personal service is not practicable, the notice shall be served on such Government servant by registered post acknowledgement due at the address of the Government servant available with the appointing authority. If the notice sent by registered post is returned unserved, it shall be published in the Official Gazette and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such Government servant on the date it was published in the Official Gazette.
- (2) (a) Where a notice is given by the appointing authority terminating services of a temporary Government servant, or where the services of any such Government servant is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowances, the Central Government or any other authority specified by the Central Government in this behalf may, of its own motion or otherwise, re-open the case, and after calling for the records of the case and after making such inquiry as it deems fit,
- (i) confirm the action taken by the appointing authority
- (ii) withdraw the notice;
- (iii) reinstate the Government servant in service; or
- (iv) make such other order in the case as it may consider proper;

Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be reopened under this sub-rule after the expiry of three months.—

- (i) from the date of notice, in a case where notice is given;
- (ii) from the date of termination of service, in a case where no notice is given.

- (b) Where a Government servant is re-instated in service under sub-rule (2) the order of re-instatement shall specify:—
- (i) the amount or proportion of pay and allowances if any, to be paid to the Government servant for the period of his absence between the date of termination of his services and the date of his re-instatement; and
- (ii) whether the said period shall be treated as a period spent on duty for any specified purpose or purposes”.

9. The Government of India examined the complaint's of the National Council in respect of payment of one month's pay in lieu of notice and made the following decision vide C.S., Department of Personnel, No. 4/2/72-Ests. (C), dated the 4th November, 1972.

“(5) Pay and allowances to be paid immediately on discharge.—The undersigned is directed to invite the attention of the Ministry of Finance etc., to the Notification of the Department of Personnel No. 4/2/72-Ests. (C), dated the 23rd June, 1972 amending the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the C.C.S. (T.S.) Rules, 1965. With this amendment, the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 would read as follows:—

“Provided that the services of any such Government servant may be terminated forthwith and on such termination the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, as the case may be, for the period by which such notice falls of the month”

2. The amendment introduced by the aforesaid Notification came up for discussion in the meeting of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery in its meeting held on the 28th and 29th July, 1972. During the discussion the Staff Side inter alia pointed out that the amendment might lead to delay in making payment of pay and allowances in lieu of notice to temporary Government servants discharged summarily. In order to allay this apprehension, it was agreed by the Official Side that although the amended proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the C.C.S. (T.S.) Rules, 1965 provides that upon the termination of services of a temporary Government servant forthwith, he would be entitled to claim his pay and allowances in lieu of notice, executive instructions would be issued to the effect that the Ministries/Departments should make payment of pay and allowances to such Government servants immediately on their discharge.

3. The agreement reached in the National Council is brought to the notice of the Ministry of Finance, etc., for issuing suitable instructions to the appointing authorities under them”.

10. The situation, thus, is that the termination of service of Rattan is legal, but there is a lack of justification in the matter of payment of notice paid to him, which was offered to him only in the year 1980 and which he refused. Therefore, the workman is entitled to compensation in respect of delayed offer of compensation due to him under C.C.S. (T.S.) Rules, 1965. The matter referred to this tribunal is not only the legality but also the justifiability and fairness of the action taken by the Central Telegraph Office, Kanpur

11. Non-payment of notice-pay, in lieu of notice for one month to the workman is both unjust and unfair and is in contravention of the Department of Personnel Directive dated 4-11-72 referred to above.

12. The Post & Telegraph office is offering services to the Community, which even a private agency can provide

and it is not discharge of sovereign function of the State and, therefore, Rattan must be accepted as a workman and Central Telegraph Office shall be accepted as an “Industry” as the terms defined in I.D. Act, 1947 and the Central Government Industrial Tribunal has jurisdiction in the matter.

13. Under the situation aforesaid, the action of the management in terminating the services of Rattan is upheld as legal, but non-payment of compensation to him and non-tender of it till 1980 is held to be both unfair and unjustified. In the result, the management is directed to pay him compensation in the amount of Rs. 4000/- for non-compliance with the requirement of the proviso to section 5(i) of the C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965 till the year 1980 and a direction is made accordingly. The case of Smt. Chandrawati Vs. Superintendent of Post Offices, New Delhi, I.D. No. 63/83 decided by this Tribunal on 12-1-84 is distinguishable. She was a Daily Wager and the C.C.S. (Temporary Service) Rules do not apply to government servants not in whole time employment and to government servants engaged on contract as also they do not apply to government servants paid out of the contingencies.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

27th March, 1984

[No. L-40012 (5)/79 D.II (B)]

O.P. SINGLA, Presiding Officer

S.O. 1411.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Delhi Milk Scheme and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th March, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW

DELHI

I.D. No. 2 of 1981

In the matter of dispute between

BETWEEN

The Convener,  
Joint Action Committee,  
Delhi Milk Scheme,  
West Patel Nagar,  
New Delhi-110008.

Versus

The General Manager,  
Delhi Milk Scheme,  
West Patel Nagar,  
New Delhi.

APPEARANCES

Shri Narinder Chaudhary—for the Management.  
Shri R. S. Rawat—for the Workmen.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-42011(10)/80-D. II(B) dated 6th January, 1981, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

“Whether the action of the management of Delhi Milk Scheme, New Delhi, in not regularising all the daily-paid workmen, who have completed requisite attendance in accordance with the Government Rules, as Mates, is justified? If not, to what relief are these workmen entitled?”

“Whether the action of the management of Delhi Milk Scheme New Delhi, in asking the Mates working in the Transportation Department to wash the

Milk Vans after unloading is justified and legal ?  
If not, to what relief are the workmen entitled ?

2. The Joint Action Committee of Delhi Milk Scheme Employees Union in the claim statement submitted to this Tribunal pleaded that the Daily paid workers working in Delhi Milk Scheme were selected, after being sponsored by the Regional Employment Exchange. They worked for 5 to 6 years, and completed more than 240 days attendance in 12 months. The work for which they were appointed, and which they have been doing for the last 5-6 years, is of continuous nature and not time-bound. The Management had the practice of regularising the Daily Paid Workers on completing 240 days attendance in 12 months, and all the eligible Daily Paid Workers appointed by the Delhi Milk Scheme had already been regularised and worked as regular workers. The present batch of Daily Paid Workers is the only group which has not been given the benefit of regularisation, despite working for a number of years. The denial of regularisation of these workmen is said to be discriminatory and the discrimination was required to be removed forthwith by appointing all the Daily Paid Workers on regular basis. The request was made that they be made regular w.e.f. 21-1-80, when the Charter of Demands was submitted.

3. The management contested the claim and stated that the Badli Workers of Delhi Milk Scheme were those who were employed for the purpose of work in place of regular employees, who were temporarily absent. The certified Standing Orders mentioned that "a Badli Worker who has actually worked for not less than 240 days in any period of 12 months should be transferred to regular establishment governed by R. S. and S. S.". This matter was taken up in 1971 with the Ministry of Law who observed that such regularisation should be done only if vacancies were available. It was not possible to regularise all Badli Workmen who had completed 240 days attendance during a period of 12 months. The Badli Workmen were being brought to regular establishment as and when vacancies occur. In the year 1980, 40 Badli Workers were brought over to the regular posts of Mates.

4. In respect of the other demand raised by the Workmen it was submitted that the duty of Washing the Vans was included alongwith the loading and unloading of the bottles, crates and cans in milk vans in the Recruitment Rules for the post of mates notified by the Government of India. The utilisation of the services for washing and cleaning of Milk Vans could not be challenged as it was within the scope of the award of the management and their condition of service.

5. The second demand in respect of washing and cleaning of milk vans has been given up by the workmen before this Tribunal, and the only question to be decided is with respect to the first demand of regularisation.

6. The certified standing orders in para 4(ii) provide that "a badli worker who has actually worked for not less than 240 days in any period of 12 months shall be transferred to regular establishment governed by the Fundamental and Supplementary Rule". There is nothing in the Recruitment Rules dated 15-7-64 to the contrary, and the Middle-Standard-Pass persons in good health are eligible for appointment as Mates.

7. The workmen have approached this Industrial Tribunal only because the standing orders are not being obeyed and they have not been regularised, in spite of the clear mandate of the standing orders of Delhi Milk Scheme referred to earlier. The opinion of the Law Department, Govt. of India that regularisation should await happening of a vacancy is not acceptable, because the standing orders do not require that such regularisation should happen only on occurring of a vacancy in the regular establishment. The standing orders ordain transfer to regular establishment on completion of 240 days service in any period of 12 months, and require no other formality.

8. The claim made by these Badli workmen is sound and legal and is in accordance with the standing orders of the Management of Delhi Milk Scheme. The refusal of

Delhi Milk Scheme Management to honour the standing orders is not understood. The Management of Delhi Milk Scheme is directed to make all these Badli Workmen regular w.e.f. 21-1-80, when the demand was lodged with the Management and the Management should create posts for their regularisation in the regular establishment since that date.

9. The workmen shall also be entitled to Rs. 100 as the quantified costs of this reference.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

March 24, 1984.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-42011/10/80-D. II(B)]

S.O. 1412.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Telegraph Office, Kanpur and their workman, which was received by the Central Government on the 29th March, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 118/80

In the matter of dispute between

Shri Murli S/o. Shri Ram Pershad, Or. No. 293,  
C.P.C. Goods, Sheds Northern Railway, Near  
Collectorganj, Canteen, Kanpur

Versus

The Union of India, through Superintendent Incharge,  
Central Telegraph Office, The Mall, Kanpur.

APPEARANCES :

Shri Narendra Chaudhary—for the Central Telegraph  
Office.

Shri A. P. Anand—for the workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. 40012(4)/79-D. II.B dated 21st October, 1980, referred the following disputes to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Superintendent Incharge Central Telegraph Office, Kanpur in terminating the services of Shri Murli Sweeper with effect from 30-6-1978 is fair, just and legal. If not, to what relief the workman is entitled?"

Mr. Murli was appointed on 1-9-76 as non-test candidate in class IV and had his service terminated on 6-1-77. Thereafter he was re-appointed on the forenoon of 7-1-77 and continued working upto 30-6-78 as officiating Sweeper. His services were terminated and his case is that he was not given any notice-pay nor any retrenchment compensation to which he was entitled under section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947. He claimed reinstatement in service with full back wages and continuity of service. He also pleaded that the action of the management was mala fide.

3. The Management contested the claim and asserted that the Central Telegraph Office was not 'an Industry' as the term is defined in Industrial Disputes Act, 1947. Mr. Murli was said to be not entitled to the benefit of Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 and the C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965 were relied upon. He was offered one month's notice-pay in lieu of notice which he refused. It was claimed that no junior officials were retained and Kamla Kant was senior to him in the year of

selection and so was Ravindra. Smt. Suresh and Durga Devi were appointed in a different category in relaxation of rules and on compassionate grounds, because their husbands died during service.

4. The workman gave his own statement and has been cross-examined. The Central Telegraph Office filed affidavit of its Superintendent A. Chinnakkani and he has been cross-examined by the workman. I have heard the representative of the parties.

5. The workman Shri Murli did work for more than 240 days during the period 7-1-77 to 30-6-78 and ostensibly claims benefit of protection of section 25-F of I.D. Act, 1947.

6. There is a recent judgment of Patna High Court Full Bench in case R. K. Bharati Vs. State of Bihar and others (1983 Lab I.C. 1884) where the applicability of section 25-F I.D. Act, 1947, Government Department is examined. It reads there as under :—

"If there are enactment, or rules framed under Art. 309 of the Constitution, which either expressly or by necessary implication exclude the operation of the Industrial Disputes Act, no question of applicability of the provisions of the Act arises. The mere fact that there is a Service Code dealing with some of the aspects of the employer-employee relationship between the Government and its Employees does not amount by necessary implication to the exclusion of the provisions of the Act to Government Departments. If there were rules, for instance, specifically dealing with the manner in which temporary appointments could be terminated, it could legitimately be argued that S-25F of the Act is excluded. For then, the rules framed under the constitutional provisions would have precedence over the provisions of the Act. It is not possible to accept the extreme contention that the provisions of the Industrial Disputes Act do not at all apply to Government Servants".

7. The appointment of Murli was not as a Daily-paid worker but on a regular scale, and he must be accepted as a temporary servant under C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965, and section 5 of these rules applied to him, and these rules are made under Article 309 of the Constitution of India and they eliminate the applicability of section 25F of I.D. Act, 1947.

8. Section 5 of the C.C.S. (Temporary Service) Rules is in the following terms, on account of the amendment made in 1972.

"5. (1)(a) The services of a temporary Government servant who is not in quasi-permanent service shall liable to termination at any time by a notice in writing given either by the Government servant to the appointing authority or by the appointing authority to the Government servant;

(b) the period of such notice shall be one month;

Provided that the service of any such Government servant may be terminated forthwith (and on such termination the Government servant shall be entitled to claim) a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his services, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

Note.—The following procedure shall be adopted by the appointing authority while serving notice on such Government servant under clause (a) :—

(i) The notice shall be delivered or tendered to the Government servant in persons;

(ii) Where personal service is not practicable, the notice shall be served on such Government servant by registered post acknowledgement due at

the address of the Government servant available with the appointing authority. If the notice sent by registered post is returned unserved, it shall be published in the Official Gazette and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such Government servant on the date it was published in the Official Gazette.

(2) (a) Where a notice is given by the appointing authority terminating services of a temporary Government servant, or where the services of any such Government servant is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowances, the Central Government or any other authority specified by the Central Government in this behalf may, of its own motion or otherwise, re-open the case, and after calling for the records of the case and after making such inquiry as it deems fit,—

(i) confirm the action taken by the appointing authority;

(ii) withdraw the notice;

(iii) reinstate the Government servant in service; or

(iv) make such other order in the case as it may consider proper;

Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be re-opened under this sub-rule after the expiry of three months :—

(i) from the date of notice, in a case where notice is given;

(ii) from the date of termination of service, in a case where no notice is given.

(b) Where a Government servant is re-instated in service under sub-rule (2) the order of re-instatement shall specify :—

(i) the amount or proportion of pay and allowances if any, to be paid to the Government servant for the period of his absence between the date of termination of his services and the date of his re-instatement; and

(ii) whether the said period shall be treated as a period spent on duty for any specified purpose or purposes".

9. The Government of India examined the complaint of the National Council in respect of payment of one month's pay in lieu of notice and made the following decision vide C.S., Department of Personnel, No. 4/2/72-Ests.(C), dated the 4th November, 1972.

"(5) Pay and allowances to be paid immediately on discharge.—The undersigned is directed to invite the attention of the Ministry of Finance etc., to the Notification of the Department of Personnel No. 4/2/72-Ests.(C), dated the 23rd June, 1972 amending the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the C.C.S. (T.S.) Rules, 1965. With this amendment, the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 would read as follows :—

"Provided that the services of any such Government servant may be terminated forthwith and on such termination the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of the month".

2. The amendment introduced by the aforesaid Notification came up for discussion in the meeting of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery in its meeting held on the 28th and 29th July, 1972. During the discussion the Staff Side inter alia pointed out that the amendment might lead to delay in making payment of pay and

allowances in lieu of notice to temporary Government servants discharged summarily. In order to allay this apprehension, it was agreed by the Official Side that although the amended proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the C.C.S. (T.S.) Rules 1965 provides that upon the termination of services of a temporary Government servant forthwith, he would be entitled to claim his pay and allowances in lieu of notice, executive instructions would be issued to the effect that the Ministries/Departments should make payment of pay and allowances to such Government servants immediately on their discharge.

3. The agreement reached in the National Council is brought to the notice of the Ministry of Finance, etc., for issuing suitable instructions to the appointing authorities under them."

10. The termination of service of Murli is seen to be legal under section 5 of the C.C.S. (T.S.) Rules, 1965, but there is lack of justification fairness in the matter of payment of notice-pay to him, which is offered to him in the year 1980 and which he refused. Therefore, the workman is entitled to compensation in respect of delayed offer of compensation which was due to him under C.C.S. (T.S.) Rules, 1965. The matter referred to this tribunal is not only the legality but also the justifiability and fairness of the action taken by the Central Telegraph Office, Kanpur.

11. Non-payment of notice-pay, in lieu of notice for one month, to the workman is both unjust and unfair and is in contravention of the Department of Personnel Directive dated 4-11-72 referred to above.

12. The Post & Telegraph Office is offering services to the Community, which even a private agency can provide, and it is not discharge of sovereign function of the State and, therefore, Murli must be accepted as a workman and Central Telegraph Office shall be accepted as an 'Industry' as the term is defined in I.D. Act, 1947, and the Central Government Industrial Tribunal has jurisdiction in the matter.

13. It, thus, appears that the action of the management in terminating the services of Murli has to be accepted and upheld, as legal but non-payment of compensation to him and non-tender of it till 1980 is held to be both unfair and unjustified. In the result, the management is directed to pay him compensation in the amount of Rs. 4000 for non-compliance with the requirement of the proviso to section 5(i) of CCS (Temporary Service) Rules, 1965 till the year 1980, and a direction is made accordingly. The case of Smt. Chandrawati Vs. Superintendent of Post Offices, New Delhi I.D. No. 63/83 decided by this Tribunal on 1-1-84 is distinguishable. She was a Daily-Wager and the C.C.S. (Temporary Service) Rules do not apply to government servants not in whole-time employment and to government servants engaged on contract as also they do not apply to Government servants paid out of the contingencies.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

C. P. SINGLA, Presiding Officer

March 27, 1984

[No. L-40012(4)/79-D.II(B)]

T. B. SIFARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1984

का० आ० 1413 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी लखवाव नगरिक सहकारी बैंक लि० लखवाव डिस्ट्रिक सहसंस्थान (एन० जी०) नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(78)/84/पी० एक-2]

New Delhi, the 11th April, 1984

S.O. 1413.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Lakhwad Nagrik Sahkari Bank Ltd., Lakhwad, Dist. Mehsana (N.G.) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(78)/84-PF.III]

का० आ० 1414 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्द्रावादन चन्द्र शंकर, यु० एम० मिस्त्री कम्पाउंड, नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, बापु नगर, अहमदाबाद-23 नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(75)/84/पी० एक-2]

S.O. 1414.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indravadan Chandrashanker, U.M. Mistry Compound, Near Industrial Estate, Bapunagar, Ahmedabad-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(75)/84-PF.III]

का० आ० 1415 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हंसा टेक्सटाइलस यु० एम० मिस्त्री कम्पाउंड, नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, बापु नगर, अहमदाबाद-23 नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(89)/84/पी० एक-2]

S.O. 1415.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hansa Textiles, U.M. Mistry Compound, Near Industrial

Estate, Bapunagar, Ahmedabad-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(69)/84-PF.II]

का० आ० 1416:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी न्यू डुरास इन्डस्ट्रीज गली नं० 3, 39/16, समैपुर बादली, दिल्ली-42 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(70)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 1416.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. New Duracs Industries, Gali No. 3, 39/16, Samaipur Badli, Delhi-110042 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(70)/84-PF.II]

का० आ० 1417:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंटरनेशनल सिस्टम सर्विसेस प्रा० लि० 203-204, सरस्वती हाउस, 27-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(71)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 1417.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. International System Services Private Limited, 203-204, Saraswati House-27, Nehru Place, New Delhi-19 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(71)/84-PF.II]

का० आ० 1418:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 47, बंगला रोड, कमला नगर, दिल्ली-110007 और इसका शाखा कार्यालय 4332/1, निमर बी० डी० हाई स्कूल, अम्बाला कैंट नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(72)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 1418.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Gupta Traders 47-Bungalow Road, Kamla Nagar, Delhi-110007 including its Branch Office at 4332/1, near B. D. High School Ambala Cantt. have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(72)/84-PF.II]

का० आ० 1419:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुखराय फैब्रिक्स, यू० एम० मिस्ट्री कंपाउंड, निमर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बापु नगर अहमदाबाद-23 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(77)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 1419.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sukhrai Fabrics, U.M. Mistry Compound, near Industrial Estate, Bapunagar, Ahmedabad-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(77)/84-PF.II]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

का० आ० 1420:—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इससे उपाय प्रमुखों में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के कारखानों के कर्मचारी अन्यथा उन प्रमुखियों को प्राप्त कर रहे हैं, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रमुखियों के सारतः समरूप हैं;

प्रतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 91क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां०आ० 1700, तारीख 2 मार्च, 1983 संख्या 3038, 15 जुलाई, 1983 और संख्या 3210, तारीख 30 जुलाई 1983 के अनुक्रम में पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 1 अक्टूबर, 1983 से 30 सितम्बर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन से उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

- (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे, या नहीं; या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिकलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

- (क) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे, जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक को, ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

(ब) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रहे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बहियाँ या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

#### अनुसूची

क्र०सं०	कारखाने का नाम	संबंधित मंत्रालय/विभाग
1	2	3
1.	मास मेलिंग प्रेस, मास मेलिंग युनिट, मधुरा मार्ग, नई दिल्ली।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग)
2.	ग्राल इण्डिया इस्टीमेट आफ फिजीकल मेडीसिन एण्ड रिहैबीलिटेशन, मुम्बई की प्रास्पेक्टिक कर्मशाला।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग)
3.	गवर्नमेंट ओपियम एण्ड ऐल्के-साइड बर्से, गाजीपुर।	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
4.	व्यूकिलयर फ्यूअल काम्पलेक्स, हैदराबाद।	परमाणु ऊर्जा विभाग
5.	कलकत्ता, मुम्बई और जबलपुर स्थित संचार कारखाने।	संचार मंत्रालय (डॉक तार बोर्ड)
6.	सरकारी तार भण्डार मुम्बई	संचार मंत्रालय (डॉक तार बोर्ड)
7.	डॉक तार मोटर सर्विस कर्मशालाएं, मुम्बई।	संचार मंत्रालय (डॉक तार बोर्ड)
8.	अपस्क उठाई घर राई संयंत्र स्थल कर्मशाला विशाखापत्तनम, पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम।	नौवहन और परिवहन मंत्रालय
9.	मौसम विज्ञान संबंधी कर्मशाला, पुणे।	पर्यटन और बागर विमानन मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
10.	ज्योडेसीय और अनुसंधान शाखा कर्मशाला, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून।	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
11.	सर्वेक्षण निदेशालय (ए०आर० आर०) मुद्रण प्रेस, नई दिल्ली।	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
12.	सं० 104 (4 वी० डी०) मुद्रण समूह, भारतीय सर्वेक्षण मार्ग-दमी नक्शा उत्पादन संयंत्र, हैदराबाद।	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
13.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर।	निर्माण और आवास मंत्रालय
14.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी।	निर्माण और आवास मंत्रालय
15.	भारत सरकार पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़।	निर्माण और आवास मंत्रालय
16.	भारत सरकार फोटोमिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद।	निर्माण और आवास मंत्रालय
17.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, मैसूर-11।	निर्माण और आवास मंत्रालय
18.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, प्रौद्योगिक एस्टेट घोखला, दिल्ली।	उद्योग मंत्रालय



1	2	3
19. केन्द्रीय कुक्कुट प्रभिवर्जन कार्य, जण्डौगढ़।	कृषि विभाग	
20. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	

[संख्या एम-38014/11/83-एल० आई०]

## स्वाटीकारक नापन

इस मामले में छूट की मंजूरी के लिए, प्राधान्यता देर से प्राप्त हुआ था, इसलिए छूट को शून्यवर्ती प्रभाव देना आवश्यक ही गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को शून्यवर्ती प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 12th March, 1984

S.O. 1420.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the factories, specified in the Schedule annexed hereto, belonging to the Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 read with section 91A of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1700 dated the 2nd March, 1983, No. 3038 dated the 15th July, 1983 and No. 3210 dated the 30th July, 1983 the Central Government hereby exempts the factories specified in column 2 of the Schedule aforesaid, from the operation of the said Act for a further period with effect from the 1st October, 1983 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in

charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

## SCHEDULE

Sl.No.	Name of the Factory	Ministry/Department concerned
1	2	3
1.	Mass Mailing Press Mailing Unit, Mathura Road, New Delhi.	Ministry of Health and Family Welfare (Department of Family Welfare)
2.	Prosthetic Workshop of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay.	Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health)
3.	Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur.	Ministry of Finance (Department of Revenue)
4.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	Department of Atomic Energy.
5.	Telecommunication Factories at Calcutta, Bombay and Jabalpur.	Ministry of Communication (Post and Telegraph Boards)
6.	Government Telegraph Stores, Bombay.	Ministry of Communications (Post and Telegraph Boards)
7.	Posts and Telegraphs Motor Service Workshop, Bombay.	Ministry of Communications (Post and Telegraph Boards)
8.	Ore Handling Plant Site Workshop, Visakhapatnam, Port Trust, Visakhapatnam.	Ministry of Shipping and Transport.
9.	Meteorological Workshop, Poona.	Ministry of Tourism and Civil Aviation.
10.	Geodetic and Research Branch Workshop, Survey of India, Dehradun.	Department of Science and Technology.
11.	Directorate of Survey (AIR) Printing Press, New Delhi.	Department of Science and Technology.
12.	No. 104 (4BD) Printing Group, Pilot Map Production Plant Survey of India, Hyderabad.	Department of Science and Technology.
13.	Government of India Press, Coimbatore.	Ministry of Works and Housing.
14.	Government of India Press, Koratty.	Ministry of Works and Housing.
15.	Government of India Text Books Press, Chandigarh.	Ministry of Works and Housing.
16.	Government of India Photo Litho Press, Faridabad.	Ministry of Works and Housing.
17.	Government of India, Text Book Press, Mysore-11.	Ministry of Works and Housing.

1	2	3
18. Small Industries Service Institute, Industrial Estate, Okhla, Delhi.	Ministry of Industries.	
19. Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh.	Department of Agriculture.	
20. Bank Note Press, Dewas	Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).	

[No. S-38014/11/83-HI]

## EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1984

का० आ० 1421.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2960, तारीख 5 अगस्त, 1982 के क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन विभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में 1 जुलाई, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

पूर्योक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) उपरोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दर्ज किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रवृत्ति प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदल अभिव्यक्तियों के आधार पर हकदार हो आते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिव्यक्ति पहले ही संदल किए जा चुके हैं, तो वे आपन नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की वास्तविकता के दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ देने प्राम्ग में और ऐसी विनिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की वास्तविकता देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी:—

- (क) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की वास्तविकता की गई किसी विवरणी की विनिष्टियों को स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
- (ख) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

- (ग) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि फर्म-चारी, नियोजक द्वारा दी गई उनप्रवृत्तियों को, जो ऐसी प्रवृत्ति हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- (घ) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उगकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का गुणित्युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एन-38014/4/82-एन० आई०]

## स्पष्टीकरण

इस मामले में छूट को भूतलकी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर में प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलकी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 1421.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2960 dated the 5th August, 1982 the Central Government hereby exempts the regular employees of Electronic Data Processing Department of the Life Insurance Corporation of India, Bombay from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it, in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to said factory.

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/82-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1422.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और अधिसूचना संख्या का० आ० 3206, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अन्तर्गत में हिन्दुस्तान

एण्डोवायटिक्त लिमिटेड, पिम्परी, पुणे को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट भी शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हमें इनके पत्रानुसार उक्त अवधि उहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रश्न में और ऐसी विनिर्दिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—
  - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विनिर्दिष्टियों को गत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
  - (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में देने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या
  - (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकारों या सेवक को, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या, ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का दृष्टिकोण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज को नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एम-38014/20/83-एच. आई.]

## स्पष्टीकरण

## EXPLANATORY MEMORANDUM

इस मामले में छूट के आवेदन पर के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया है इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1422.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification No. S.O. 3206, dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Pune, from the operation of the said Act for a further period of one year from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other premises.

[No. S-38014/20/83-HI]

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1423.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के संघ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3203 तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मशाला, लाङ्गरी तथा पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1983 से 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2: उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पञ्चाभिधान दर्शाते दिए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत् अभिधानों के आधार पर हकदार हो जाते :
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिव्यक्ति पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विधिनिष्ठियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :—
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विधिनिष्ठियों को स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
  - (ii) यह अभिविधित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
  - (iii) यह अभिविधित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उस सुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिकूलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अभिविधित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दें जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभाग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजूरी के संबंध से संबंधित ऐसी लेखावटियाँ और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदाधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दें जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिन्के बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदाधारी के पास यह विश्वास करने का दृष्टान्तपूर्ण कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखावट या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस०-38014/26/83-एच० आई०]

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलसी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट भूतलसी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1423.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3203 dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Workshop, Laundry and the Department of Rehabilitation and Artificial Limbs of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1983 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other

official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) Varying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefit provided by the employer in cash and kind benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory.
- be empowered to—
- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary;
  - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
  - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official reasonable cause to believe to have been an employee; or
  - (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/26/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1423. —केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मॉसर्स सेवानल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 23 अक्टूबर, 1975 से 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिसमें यह शारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाधिधान दर्शित किए जाएंगे,
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएँ प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिनियम द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व मदत अनिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अनिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसमें इसमें

इसके पश्चात् उक्त अवधि कड़ा गया है) ऐसी विवरणियाँ एम प्रमप में और ऐसी निगमिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या धन निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—
- (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विनिर्दिष्टियों को मर्यादित करने के प्रयोजनों के लिए, या
- (ii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
- (iii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुखियों को, जो एम प्रमुखियाँ हैं जिनके प्रतिकलस्त्रण इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तब और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- (iv) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उक्त अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रयुक्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए यत्नकृत होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधीन में के किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेजों, जैसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उनके अधिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिनके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का व्यक्तिगत कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस०-38014/17/82-एच० आई०]

स्टण्टीकरण शापन

इस मामले में छूट के लिए प्रार्थना-पत्र देर से प्राप्त हुआ था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1424.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of the M/s. National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur from the operation of the said Act for a period with effect from the 23rd October, 1975 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter refer to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;
- be empowered to
- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/17/82-HI]

## EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late, however, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1425 ---केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3207, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुसार में, दामोदर वैली कारपोरेशन के (1) 132 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन, कुमार्धुबी, (2) 132 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन, नई सराय रामगढ़ और (3) दामोदर वैली कारपोरेशन सब-स्टेशन, हावड़ा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :--

- (1) उक्त कारखाने का निरीक्षक, उस अवधि की अवधि जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रकरण में और ऐसी विशिष्टियाँ सहित देना जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त उक्त अवधि की दायित्व देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :--
  - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की दायित्व दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
- (2) यह अभिविधित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
- (3) यह अभिविधित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तत्पक्ष में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या
- (4) यह अभिविधित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए गणक होगा :--

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभागाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और भगदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा

करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तिपूर्ण कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें उद्घरण लेना।

[संख्या एम०-38014/28/82-एच० आर्०]

स्पष्टीकारक आदेश

इस मामले में छूट को भूलवशी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूलवशी प्रभाव देने में किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1425.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3207 dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts (1) 132 K. V. Grid Sub-station, Kumardhubi (2) 132 K. V. Grid Sub-station, Naasarai Ramgarh and (3) Damodar Valley Corporation sub-station, Howrah belonging to the Damodar Valley Corporation from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period) such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of,—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said Act for the period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in-charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/28/82-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However it is certified that grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1426.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3202, तारीख 30 जुलाई 1983 के क्रम में, राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की, अवधि में यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट को एतों निम्नलिखित है, अर्थात् :—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रका में और ऐसी विधिद्वियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (2) नियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या नियम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—
  - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की शायद ही गई किसी विवरणी की विधिद्वियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
  - (2) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा क्या अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (3) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही

है, तबसे में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

- (4) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए, सम्मत होता है :—

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एम०-38014/22/83-एच० आई०]

#### सरकारीकरण प्राप्ति

इस मामले में छूट के आबेदन के सम्बन्ध में कार्यवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलसी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलसी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1426.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3202, dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Bombay from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) regulations, 1950;
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or



- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) take copies of or take extracts from any register account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/22/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

क्रा० प्रा० 1427.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का. 34) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्रा० प्रा० 2421, तारीख 8 जनवरी, 1982 के क्रम में मैमर्स भेजना टैक्नाइज्ड कारपोरेशन (तमिलनाडु और पांडिचेरी) लिमिटेड कोयम्बतूर, भारत सरकार का उद्यम के प्रधान कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 प्रक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्जित किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत्त अधिनियमों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पड़ती हो संवत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विनिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 का उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदाधारी,—

- (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विनिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

- (ii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

- (iii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इन अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तत्काल और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

- (iv) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अभ्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अभ्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसी लेखाबतियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदाधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

- (ग) प्रधान नियोजक या अभ्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदाधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना; या

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबतियों या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस०-380/14/39/82-एच०आई०]

स्पष्टीकारक आपन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि, छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1427.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) hereinafter referred to as the said Act, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 242 dated the 8th January, 1982, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Head Office of M/s. National Textile Corporation (Tamil Nadu and Pondicherry Limited, Coimbatore, a Government of India enterprise, from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory
 be empowered to—
  - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
  - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
  - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other documents maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/39/82-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० प्रा० 1428 —केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1701, तारीख 2 मार्च, 1983 के क्रम में मैसर्स नैटिलेक्स एंड हैडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के एककों, जो (i) रोड संख्या 2 से 5 नंबर 11 ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और (ii) रवर्णन बिल्डिंग, 14 ग्लाड्स रोड, मद्रास 14 में स्थित है जिसका कारखाना गिड्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मद्रास स्थित है) के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जनवरी 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात्—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शाए जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवर्तन होने की तारीख से पूर्व संवत्त अधिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अधिदाय पहले ही संवत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और एतों विशिष्टियों सहित देगी जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि को बाबत देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
  - (ii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा दया अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
  - (iii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिकलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तब और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में

अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजूदरी के सदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक को या ऐसे कितने व्यक्ति का या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाय, या ऐसे कितने व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्म-कारी है, परीक्षा करना, या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/8/83-एचआई]

#### स्पष्टीकारक शायन

इस मामले में छूट को भूतलजी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किंतु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलजी प्रभाव देने से कितनी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1428.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1701 dated the 2nd March, 1983 the Central Government hereby exempts the regular employees of the units of M/s. Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi located at (i) Shed number 2 to 5, Sector II-A, Noida (Uttar Pradesh) and (ii) Sundershan Building, 14, Whites Road, Madras-14 (with factory at Guindy Industrial Complex, Madras) from the operation of the said Act for a period with effect from the 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form

and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption had reasonable cause to believe to have been interest of anybody adversely.

का० आ० 1429.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नागर विमानन विभाग के मैसर्स रेडियो कंसर्वेशन यूनिट वर्कशॉप 1 नई दिल्ली के कर्मचारी उन प्रमुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रमुविधाओं के सारतः समरूप हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 91क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 244, तारीख 8 जनवरी, 1982 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् उपरोक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 1 अक्टूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1985 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बातें जिनके दौरान वह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियों ऐसे प्ररूप और विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बातें देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—
  - (i) उक्त अवधि की बातें धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
  - (ii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (iii) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएँ हैं जिनके प्रतिकलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नक़द और वस्तु रूप में पाने का हक़दार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधाननियोजक या अभ्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे जो वह आवश्यक समझे;
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अभ्यवहित नियोजक के अभिभाग में के किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेख, बहियों और अन्य वस्तुओं से ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे, या वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अभ्यवहित नियोजक की, जिसके अधिकार या सेवक का या ऐसे किसी व्यक्ति का जो ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखा बही या अन्य वस्तुओं की नक़ल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस 38014/24/83-एचआई]

स्पष्टीकारक आपन

इस मामले में छूट के लिए प्रार्थनापत्र देर से प्राप्त हुआ था इसलिए  
(1) व भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया

जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1429.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the M/s. Radio Construction unit Workshop New Delhi belonging to civil Aviation Department are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 read with section 91A of the said Act, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 244 dated the 8th January, 1982, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a period with effect from the 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory; by empowered to—
- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other, or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/24/83-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It was become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० भा० 1430.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91A के माध्यम से 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० भा० 156, तारीख 4 जनवरी, 1982 के क्रम में भारतीय भूबैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर के इंजीनियरी प्रभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसूचिदाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत् अभिवार्यों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अधिदाय पहले ही किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि को बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी-विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—
  - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत की गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ;
  - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल, स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अन्यवहित्त नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है;
- (ख) ऐसे प्रधान या अन्यवहित्त नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे

निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

- (ग) प्रधान या अन्यवहित्त नियोजक को, उनके अधिकारों या सेवाक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज को नकल तैयार करना या उसमें उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/7/83-एसआई]

#### स्पष्टीकारक शायन

इस मामले में छूट के आवेदन के सम्बंध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलधो प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलधो प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1430.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 156 dated the 4th January, 1982, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Engineering Division of the Geological Survey of India, Jaipur from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory.

be empowered to —

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S. 380(4)/7/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. It is, however, certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० अ० 1431.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3208 तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को, जो भारत सरकार का उद्यम है, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 22 जून, 1983 से 21 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक, उम अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विधिप्रणितियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधिन उक्त उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—
  - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी को विधिप्रणितियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या
  - (2) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (3) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उक्त फायदों को जिसके प्रतिफलस्वरूप

इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और नस्तुरूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं या

- (4) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए शक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उम ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अभिमोघाधीन किन्हीं कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की ओर ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबाही या अन्य दस्तावेज की तत्काल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/28/83-एच०आई०]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

स्पष्टीकारक शासन

इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतनकी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। प्रमाणित किया जात है कि छूट को भूतनकी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1431.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3208, dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts Messrs Hindustan Zinc Limited, Udaipur, a Government of India Enterprise, from the operation of the said Act for a further period with effect from the 22nd June, 1983 upto and inclusive of the 21st June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory.

be empowered to —

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/28/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. It is, however, certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1984

का०आ० 1432.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 22 अप्रैल, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्तावक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् —

“जिला शिमोगा के सागर तालुक में तालगुप्पा ग्राम की राजस्व सीमाओं के घनगंत घाते वाले क्षेत्र।”

[संख्या एम-38013/6/84-एच० आई०]

New Delhi, the 17th April, 1984

S.O. 1432.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 22nd April, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force)

of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

“The areas within the Revenue limits of Talaguppa village in Taluka Sagar, District Shimoga.”

[No. S-38013/6/84-HI]

का०आ० 1433.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 22 अप्रैल, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला जीन्द में राजस्व ग्राम किला जफरगढ़ हदबस्त नं० 26 तथा राजस्व ग्राम बुद्धा खेरा लथर हदबस्त नं० 31।”

[सं० एम-38013/5/84-एच० आई०]

S.O. 1433.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 22nd April, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

“Revenue village Kila Zafargarh, Head Bast No. 26 and Revenue village Budha, Khara Lather Had Bast No. 31 District Jind.”

[No. S-38013/5/84-HI]

का० आ० 1434 :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3205, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुसरण में, मैमर्स हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड (कानपुर डिबीजन) कानपुर, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सैक्टर उपक्रम है, को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई 1983 से 30 जून 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विनिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विनिष्टियों को मत्वापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिष्ठित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा दत्ता अपेक्षित

रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रति-फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

(4) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिसागधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनका परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में, पाया जाए या, ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उनसे उद्धरण लेना।

such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/16/83-HI]

[संख्या एम-38014/16/83-एच. आई]

स्पष्टीकरण प्राप्त

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिद्वन्द्व प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1434.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3205 dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts Messers Hindustan Aeronautics Limited (Kanpur Division) Kanpur, a public sector undertaking under the Ministry of Defence from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1983 upto and inclusive of 20th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereafter referred to as the said period), such returns in

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1435:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1555 तारीख 31 मार्च, 1982 के तम में कोल इंडिया लिमिटेड की समन्वयी कोल इंडिया प्रेम, रांची को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1982 से 30 जून 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विधिधियों सहित देगा जो



कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निम्न द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 का उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निम्न का दया निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी था—

- (1) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
- (2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
- (3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या
- (4) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अव्यवहृत नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहृत नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अव्यवहृत नियोजक को, उनके अधिकारी या सेवक को, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/4/81-एच आई.]

स्पष्टीकरण जापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि, छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1435.—In exercise of the powers conferred by section (87) read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1555 dated the 31st March, 1982, the Central Government hereby exempts the Coal India Press, Ranchi, a subsidiary of the Coal India Limited, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1982 upto and inclusive of the 30th June, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950,
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/81-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

नॉ० आ० 1436.—भारतीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना न० नॉ० आ० 3201 ता० 30 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में संसद भारत देशी एंटी एण्ड वेसेल्स लिमिटेड विनायपट्टनम को, उक्त अधिनियम के पत्रार्थ में 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक का, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2 उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाधत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रत्येक में और ऐसी विवरणियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि की बाधत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या अन्य निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाधत दी गई किसी विवरणी की विवरणियों को मत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या

(3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन प्रमुखियों-को, जो ऐसी प्रमुखियाँ हैं जिनके प्रतिकलस्वरूप इस अभिलेख सूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है; या नहीं; या

(4) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे कितनी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए, सशक्त होगा :

(क) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोगधन किम कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजूरी के संदाय में संबंधित ऐसे लेखों, बहियाँ और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अध्यक्षित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक को या, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का पुरस्कार कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस—38014/25/83-एल० आई०]

रजिस्ट्रीकरण प्राप्त

इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्यवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलश्री प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलश्री प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1436.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3201 dated the 30th July, 1983 the Central Government hereby exempts Messrs Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for further period of one year with effect from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or

any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/25/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

कां.आ. 1437.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन की-क्षेत्र कर्मचाला के कर्मचारी अन्यथा उन प्रमुखियों को प्राप्त कर रहे, है जो भारत: कर्मचारी-राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रमुखियों के समान हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा 91 क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के धर्म सलाहक की अधिसूचना संख्या कां. आ. 2959, तारीख 5 अगस्त, 1982 के क्रम में कर्मचारी-राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, उपर्युक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी है, अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट को शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक, उक्त अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रत्येक में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

- (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत ही गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या
- (2) यह अभिविनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या
- (3) यह अभिविनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिये गए उन फायरों की जिसके प्रति फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बन, हुआ है, या नहीं, या
- (4) यह अभिविनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए गणकन होगा —

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिकारीगणों किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उनके प्रसारी में यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संबंध में संबंधित ऐने, लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनके परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे, आवश्यक समझते हैं या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियत कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापना कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एम-38014/53/81-एच आई]

स्पष्टीकरण प्राप्त

इस मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन दर से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1437.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Field Workshop of Tuticorin Port Trust, Tuticorin are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90, read with section 91A of the said Act, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2959, dated the 5th August, 1982, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a period from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits, provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

- require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/53/81-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० प्रा० 1438—केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और— भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3204, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० (लखनऊ प्रभाग) लखनऊ के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1983 से 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

- पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदोन्नति दिखाए जाएंगे;
- इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुविधाएँ प्राप्त करने रहेगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के पूर्व होने की तारीख से पूर्व संश्लेष अधिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अधिदाय पहले ही किए जा चुके हों या तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे;
- उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की वास्तविकता के दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हमें हमने पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विनिर्दिष्टता सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की वास्तविकता थी;
- निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

- धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की वास्तविकता की किसी विवरणी की विनिर्दिष्टता को अन्यायित करने के प्रयोजनार्थ;
- यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा दत्त अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये या नहीं, या
- यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट से आ रहे हैं, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवर्तमान थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सज्जत होगा :—

- प्रधान या अव्यवहित नियोजक अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है;
- ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तिगत, निर्योजक और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी जिससे वे आवश्यक समझते हैं; या
- प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का शक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/21/83-एच आई]

#### स्पष्टीकारक आपन

इस मामले में छूट के आवेदन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतकाल प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतकाल प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1438.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3204, dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Hindustan Aeronautics Limited (Lucknow Division), Lucknow from the operation of the said Act for a further period with effect from the 1st October, 1983 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act, to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid, prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/21/83-II]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० जा० 14.19.83—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3039 तारीख 15 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में, सैसमें इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कांटा (राजस्थान) को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, पहली जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की ओर अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, अर्थात् :—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था। (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, जैसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि की बाबत देनी थी :
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—
  - (1) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
  - (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा गथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या
  - (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और बन्तु रूप में पाने का हक्कार बना हुआ है, या नहीं ; या
  - (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के नवबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और सज्जरी के संवाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को उसके अभिकर्ता या सेवक की ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिमर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिनके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है परीक्षा करना ;

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/17/83-एस० आई०]

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूलकी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूलकी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1439.—In exercise of the powers, conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3039 dated the 15th July, 1983, the Central Government hereby exempts M/s. Instrumentation Limited, Kota (Rajasthan) from the operation of the said Act, for a further period of one year with effect from the 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/17/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1440.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के धर्म मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 241, तारीख 8 जनवरी, 1982 के क्रम में भारत सरकार के उपक्रम मंत्रालय नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लिमिटेड, नई दिल्ली के मुख्यालय के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1982 से 30 जून 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाधिकार दर्शाए जायेंगे;
- (2) इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुखियाएं प्राप्त करने रहेंगे, जिनका पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत् अभिदायों के आधार पर हकदार हो जायें;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संवत् किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जायेंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसमें दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिस समय इसमें पश्चात् उक्त अवधि बढ़ा गया है) ऐसी विवरणियां देने प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) नियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस नियम प्राधिकृत नियम का कोई अन्य पदधारी,—
  - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए या
  - (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
  - (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुखियाओं को, जो ऐसी प्रमुखियाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में

अधिनियम के उपबन्ध प्रकृत थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक के अधिनियम में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमात्रक व्यक्ति से यह ओला-करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजूदरी के मदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/21/82-एच० आई०]

स्पष्टीकरण जापन

इस मामले में छुट की मंजूरी के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था इस लिए छुट को भूलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट को भूलक्षी प्रभाव देना किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1440.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 241 dated the 8th January, 1982, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Head Office of M/s. National Textile Corporation (Delhi, Punjab and Rajasthan) Limited, New Delhi, a Government of India Undertaking from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates,
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the

Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and record, were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books, and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/21/82-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1441—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91A के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1124, तारीख 19 मार्च, 1981 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार मार्सिंगाओ पोर्ट ट्रस्ट, मार्सिंगाओ के अधीन वर्कशाप का उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जूलाई 1981 से 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छुट देती है।

2. पूर्वाक्त छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—

- (i) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसमें हमारे इसके पश्चात् उस अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रश्न में और ऐसी विवरणियाँ सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(i) निम्न द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निम्न प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की अवधि दी गई किसी विशिष्टता की विशिष्टताओं का मन्वयित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य सेवा (नियम) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुखियों की, जो ऐसी प्रमुख-विधायक है, जिनके प्रतिकल्पस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(vi) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उप-बन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपकरणों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा.

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक के अधिभोग में के किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखाबतियों और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहृत नियोजक की, उसके अधिकारी या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास वह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबतियों या अन्य दस्तावेजों की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस०-38014/6/80 एच आई]

मार्गदर्शन ज्ञान

इन समये में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से जा रहा था। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हितपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1441.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification No. S.O. 1124 dated the 19th March, 1981 the Central Government hereby exempts the workshop under the Mormugao Port Trust, Mormugao from the operation of the said Act for the period from the 1st July, 1981 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/6/80-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 1442.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3209, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुच्छेद में नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष और अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

(i) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की यावत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे



इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—
- (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या
- (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
- (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों की, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अवधि-सूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या
- (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:-

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिमोहाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से या अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखायही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

[संख्या एम- 38014/27/83-एच० आई०]

स्पष्टीकरण जापन

इस मामले में छूट की भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1442.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour 69 GI/84—12

No. S.O. 3209 dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provision were in force in relation to the said factory ;

by empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/27/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 1443.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1947 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1560 तारीख 31 मार्च, 1982 के अनुक्रम में:-

- (1) भारत गोल्ड माईन्स प्राईवेट लिमिटेड (सेन्ट्रल वर्कशॉप), ऊरगाव पोस्ट, कोलार गोल्ड फील्ड्स (2) भारत गोल्ड माईन्स प्राईवेट लिमिटेड (ऊरगाव डेरी, ऊरगाव पोस्ट, कोलार गोल्ड फील्ड्स और (3) भारत गोल्ड माईन्स प्राईवेट लिमिटेड ऊरगाव प्रिन्टिंग प्रेस, ऊरगाव पोस्ट, कोलार गोल्ड फील्ड को पहली जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देनी है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का, नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विनिर्दिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

- (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विनिर्दिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

- (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

- (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तुरूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

- (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

भेन्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा:—

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसे जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिमोक्षाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रहे

गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[गख्या एम-38014/37/81-एच० आर्ट०]

स्पष्टीकारक जापान

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1443.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. No. 1560 dated the 31st March, 1982, the Central Government hereby exempts (1) Bharat Gold Mines Private Limited (Central Workshop), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields; (2) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaum Dairy); Oorgaum Post, Kolar Gold Field and (3) Bharat Gold Mines Private Limited Oorgaum Printing Press, Oorgaum Post, Kolar Gold Fields from the operation of the said Act for a further period from the 1st July, 1982 upto and inclusive of the 30th June, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period) such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said Act for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other offi-

cial had reasonable cause to believe to have been an employee ; or

- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/37/81-HI]

### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.० अ.० 1444—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.० अ.० 482, तारीख 19 जनवरी, 1982 के अनुक्रम में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियों ऐसे प्ररूप में और ऐसी विनिर्दिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विनिर्दिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे, या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तुरूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, या नहीं।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या

- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस० 38014/41/82 एच० आई०]

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1444.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 482 dated the 19th January, 1982 the Central Government hereby exempts Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st April, 1982 upto and inclusive of the 31st March, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said Act for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

—(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such

factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/41/82-110]

### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1445—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3211 तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुसार ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई 1983 से 30 जून 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रश्न में और ऐसी शिर्षिकाओं सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा-(1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की शिर्षिकाओं को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ या

(2) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे, या नहीं या

(3) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हक्कदार बना हुआ है, या नहीं ; या

(4) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किसी उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:

(क) प्रधान या अन्यवहित नियोजक से अपेक्षा करता कि वह उसे ऐसे जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अन्यवहित नियोजक के अधिसूचनाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तिगत रूप से नियोजन और मजदूरी के संबंध

में संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, यह उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अन्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिमर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिनके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखापत्री या अन्य दस्तावेज की तत्काल नद्वार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एम-38014 / 18 / 83-एच० आई०]

### स्पष्टीकारक शायन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति को हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1445.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3211 dated the 30th July, 1983 the Central Government hereby exempts Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, a public sector undertaking under the Ministry of Defence from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2 The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

by empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any

person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of/or take extracts from any register, accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/18/83-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1984

का० आ० 1446—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3040, तारीख 16 जुलाई, 1983 के अनुसार में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन को, जो नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई 1983 से 30 जून 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वी छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की वास्तविकता के दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की वास्तविकता देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की वास्तविकता दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :-

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे

ऐसा जानकारी दे जिससे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्ति के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है परीक्षा करना;

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखवही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एन-38014/23/83 एच० आई०]

स्पष्टीकरण जापन

इस मामले में फ्रंट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 1446.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employers' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3040 dated the 16th July, 1983 the Central Government hereby exempts the Cochin Shipyard Limited, Cochin, a Public Sector Undertaking under the Ministry of Shipping and Transport from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when

such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/23/83-III]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1447—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1918 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या आ० आ० 1510 तारीख 29 मार्च, 1982 के अनुक्रम में, दि 1 अप्रैल 1982 को एम्प्लॉयर्स लिमिटेड पी-68 सी० सी० आर० टावरसेन रोड, पहाड़पुर, कलकत्ता और दि इंडियन ऑयल ब्लेंडिंग लिमिटेड, पिर पाऊ ट्रोम्बे बम्बई -74 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई 1982 से 30 जून 1983 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विधिष्ठियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) अधिनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विधिष्ठियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
  - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) अधिनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रबन्धी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और सज्जदारी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, य, उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या
- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को उसके अधिकारी या—
  - सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रख गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसे उद्धरण लेना ।

[संख्या एम-38014 / 37 / 82-एच० आई०]

#### स्पष्टीकारक भाषण

इस मामले में छूट की भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1447.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1510, dated the 29th March, 1982, the Central Government hereby exempts the India Oil Blending Limited, P. 68 C.C.R. Diversion Road, Paharpur, Calcutta and the Indian Oil Blending Limited, Pir Pau, Trombay, Bombay-74 from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1982 upto and inclusive of the 30th June, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State

Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/37/82-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1448.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2958, ता० 5 अगस्त, 1982 के क्रम में, नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, इंदौर के रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रमुखियाएँ प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संबंधित अधिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अधिदाय पहले ही किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिस दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ

ऐसे प्रारूप में और ऐसी विधिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—
  - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विधिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ;
  - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
  - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गये उन फायदों को, जिनके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है;
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभिमोहाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संबंध से संबंधित ऐसे लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तिपूर्ण कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही, या अन्य दस्तावेज की तकन तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/52/81-एच० आई०]

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किंतु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से कितना भी व्यक्ति हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 1448.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notifica-

tion of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2958 dated the 5th August, 1982 the Central Government hereby exempts the regular employees of the registered office of the National Textile Corporation (Madhya Pradesh Limited Indore, from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees :

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/52/81-HI]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1984

का० आ० 1449.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1562, तारीख 1 अप्रैल, 1982 के क्रम में इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के इससे उपायध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक को, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विनिर्दिष्टों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उमे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विनिर्दिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या
  - (ii) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
  - (iii) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उस प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएँ हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, बचक और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उद्देश्यों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा :—

- (क) प्रधान नियोजक या अग्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अग्यवहित नियोजक के अधिभोग में किसी भी कारखानों के स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसे लेख, बहियों और अन्य वस्तुओं, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या
- (ग) प्रधान नियोजक या अग्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारों या सेवा की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावही या अन्य वस्तुओं की नकल कर या उससे उद्धरण लेना।



अनुसूची				1	2	3	4
क्र०	राज्य या संघ	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम	12.	तमिलनाडु	मद्रास	इंडियन आइल कारपोरेशन, लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कोरुकुपेट, मद्रास-21
सं०	राज्य क्षेत्र का नाम			13.	तमिलनाडु	मद्रास	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), उत्तर रेल टर्मिनल रोड, रोयापुरम, मद्रास
1	2	3	4	14.	तमिलनाडु	मद्रास	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, मीनामबक्कम विमान पत्तन, मद्रास
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम-1	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं० 54, मल्कापुरम इंस्टानेशन, विशाखापत्तनम-1	15.	तमिलनाडु	मद्रास	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, द्यूब ब्लैडिंग प्लान्ट, एनेरे हाई रोड, नेलियारपेट, निरुवेलियार डाकघर, मद्रास-81
2.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं० 1634, आर आर सी ग्राउंड, सिकंदराबाद	16.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), सरकारी खाद्यान्न गोदाम के निकट, बावला, मुम्बई-31
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), स्टेशन रोड, विजयवाड़ा	17.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), टाटा ताप विद्युत संयंत्र के पास ट्रांक्वेल, कोरोडोर रोड, मुम्बई-74
4.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद-14	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन डाकघर, हाकिमपेट वायु-सेना स्टेशन, सिकंदराबाद-14	18.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), राजबहादुर मोतीलाल रोड, पुणे
5.	दिल्ली	दिल्ली	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), एल० पी० जी० बार्टलिंग प्लान्ट, शकूरबस्ती, दिल्ली-26	19.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), सवारी रेल स्टेशन के सामने, मुम्बई-15
6.	दिल्ली	दिल्ली	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), शिवाजी पार्क के सामने, शकूरबस्ती, दिल्ली-26	20.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सांताक्रुज विमान पत्तन, मुम्बई-29
7.	दिल्ली	दिल्ली	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सवर बाजार रोड, मोर लाइन के निकट पालम, दिल्ली छावनी-10	21.	कर्नाटक	बंगलौर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), नाग दी रोड, पोस्ट बाक्स सं० 3, बंगलौर-23
8.	केरल	कोचीन	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), कोचीन पारिष्करण प्रतिष्ठान, पोस्ट बाक्स सं० 8, विजु नीय वाया कोचीन	22.	कर्नाटक	बंगलौर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन बंगलौर, विमानन पत्तन, बंगलौर
9.	केरल	कोचीन	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), कोचीन पोस्ट बाक्स सं०, 535, विलिंगटन द्वीप हारबर रोड, कोचीन-3	23.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, विमानपत्तन, हैदराबाद
10.	केरल	कोचीन	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), मशाका मार्ग, पोस्ट बैग 1759, एनाकुलम, कोचीन-16	24.	पंजाब	जालंधर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), रेल गुरुक्षेत्र रोड, जालंधर
11.	तमिलनाडु	मद्रास	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), एनोव हाई रोड, मद्रास				

1	2	3	4
25.	हरियाणा	अम्बाला छावनी	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), ब्लक सेंटर, अम्बाला छावनी
26.	हरियाणा	हिसार	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), हिसार
27.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), अरमापुर, कानपुर
28.	महाराष्ट्र	नागपुर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), मोतीबाग, नागपुर।
29.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), दम- बम विमानन ईंधन स्टेशन दम-बम विमान पत्तन, कलकत्ता
30.	पश्चिम बंगाल	पहाड़ पुर	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), पहाड़- पुर प्रतिष्ठापन, पश्चिम बंगाल
31.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), मोरी ग्राम प्रतिष्ठापन, डाकघर राधादासी, जिला हावड़ा
32.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), बज बज प्रतिष्ठापन, डाकघर बज बज, 24-परगना, पश्चिम बंगाल
33.	असम	गोहाटी	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (विपणन प्रभाग), गोहाटी प्रतिष्ठापन, गोहाटी
34.	बिहार	पटना	इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि- टेड (पटना प्रभाग), पटना प्रतिष्ठापन, पटना
35.	उत्तर प्रदेश	आगरा	इंडियन आइल कारपोरेशन लि०, (विपणन प्रभाग), खेरिया विमान क्षेत्र, आगरा-3
36.	केरल	तूतीकोरिन	इंडियन आइल कारपोरेशन लि० (विपणन प्रभाग), तूतीकोरिन प्रतिष्ठापन, बंदरगाह परि- योजना परिसर, तूतीकोरिन-4
37.	उड़ीसा	कटक	इंडियन आइल कारपोरेशन लि० (विपणन प्रभाग), शिकारपुर डाकघर बोलीगंज, कटक
38.	गोवा	वास्कोडीगामा	इंडियन आइल कारपोरेशन लि० (विपणन प्रभाग), वास्को डीगामा, गोवा
39.	कर्नाटक	मंगलूर	इंडियन आइल कारपोरेशन लि० (विपणन प्रभाग), मंगलूर प्रतिष्ठापन, मंगलूर

1	2	3	4
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	इंडियन आइल कारपोरेशन लि० (परिष्करण और पाइप लाई प्रभाग), कानपुर स्टेशन अरमापुर, कानपुर
41.	राजस्थान	जयपुर	आई ओ सी (मार्केटिंग डिवीजन) डिवीजनल आफिस चोमे हाऊस अपोजिट रेजिडेंसी, डाक घर बाक्स नं० 811, जयपुर- 302001
42.	राजस्थान	जयपुर	आई ओ सी (मार्केटिंग डिवीजन), जयपुर डिपो, जयपुर साउथ, जयपुर।

[संख्या एस-38014/29/82-एच० आई०]

## स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट के प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाग देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 18th April, 1984

S.O. 1449.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 1562, dated the 1st April, 1982, the Central Government hereby exempts the factories, specified in the Schedule annexed hereto belonging to the Indian Oil Corporation Limited, Bombay from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1982 upto and inclusive of the 30th June, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the State or Union Territory	Name of area	Name of factory
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam-I	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Post Box No. 54, Malkapuram Installation, Visakhapatnam-I.
2.	Andhra Pradesh	Secunderabad	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Post Box No. 1634, RRC Ground, Secunderabad.
3.	Andhra Pradesh	Vijaywada	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Station Road, Vijayawada.
4.	Andhra Pradesh	Secunderabad-14	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Post Office Hakimpet, Air Force Station, Secunderabad-14
5.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), L.P.G. Bottling Plant, Shakurbasti, Delhi-26.
6.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Opposite Sivaji Park, Shakurbasti, Delhi-26.
7.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Sadar Bazar Road, Near More Line, Palam, Delhi Cantt-10
8.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Cochin Re.

1	2	3	4
			finery Installation, Post Box No. 8, Tripunith via Cochin.
9.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Cochin, Post Box No. 535, Willington Island, Harbour Road, Cochin-3.
10.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Mashaka Road, Post Bag 1759, Ernakulam, Cochin-16.
11.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Errove High Road, Madras.
12.	Tamil Nadu	Maras	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Korukupet, Madras-21.
13.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), North Railway, Terminus Road, Royapuram, Madras.
14.	Tam Nadu	Madras	Indian Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Meenamobakkam Airportt Madras.
15.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Tube Blending Plant, Ennere Hig Road, Tenlarpet, Tirvethiyar Post, Madras 81.
16.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Near Government Food Grains Godowns, Wadala, Bombay-31.
17.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Near Tata, Thermal Power Plant Trombay, Corridor Road, Bombay-74.
18.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Rajbahadus Motilal Road, Poona
19.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited (Marketing division, Opposite Sewartes Railway Station. Bombay-15.
20.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Santa Cruz Airport, Bombay-29.

1	2	3	4	1	2	3	4
21. Karnataka	Bangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Nagadi Road, Post Bag No. 3, Bangalore-23.		34. Bihar	Patna	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Patna Installation, Patna.	
22. Karnataka	Bangalore	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Bangalore Airport, Bangalore.		35. Uttar Pradesh	Agra	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Khaeri, Air Field, Agra-3.	
23. Andhra Pradesh	Hyderabad	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Airport, Hyderabad.		36. Kerala	Tuticoria	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division), Tuticorin Installations, Harbour Project Premises, Tuticorin-4.	
24. Punjab	Jullundur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Railway Goods Shed Road, Jullundur.		37. Orissa	Cuttack	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Shikarpore, P. O., Chauliganj, Cuttack.	
25. Haryana	Ambala Cantonment	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Bulk Centre, Ambala Cantonment.		38. Goa	Vasco-de-Gama	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Vasco-de-Gama, Goa.	
26. Haryana	Hissar	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Hissar.		39. Karnataka	Mangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Mangalore	
27. Uttar Pradesh	Kanpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Arampore, Kanpur.		40. Uttar Pradesh	Kanpur	Indian Oil Corporation Limited, (Refineries)-and Pipe Lines Division) Kanpur I Station, Armapur, Kanpur.	
28. Maharashtra	Nagpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Moti Bagh, Nagpur.		41. Rajasthan	Jaipur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Divisional Office, Chome House, Opposite Residency, P.O. Box No. 811, Jaipur-302001.	
29. West Bengal	Calcutta	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Dum-Dum Aviation Fuel Station Dum-Dum Airport, Calcutta.		42. Rajasthan	Jaipur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Jaipur Depot Jaipur South, Jaipur.	
30. West Bengal	Paharpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Paharpur Installations, West Bengal					(No. S 38014/29/82-H)
31. West Bengal	Calcutta	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Mourigram Installations, Post Office Radhadasi, Distt. Howrah.					
32. West Bengal	24-Paraganas	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Budge Budge Installations, Post Office Budge Budge 24, Paraganas, West Bengal.					
33. Assam	Gauhati	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Gauhati Installation, Gauhati					

## EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the proposal for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. अ. 1450.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेद टेलर्स एम-81, कनाब प्लेस, नई दिल्ली नामक स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अविविध निधि और प्रकीर्ण

उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(73)/84/पी०एफ-2]

#### CORRIGENDUM

S.O. 1450.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ved Tailors, M-61, Connaught Place, New Delhi-110001, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (73)/84-PF-II]

शुद्धि पत्र

का०आ० 1451.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28 जनवरी, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के अम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना सं० 292, तारीख 9 जनवरी, 1984 के क्रम संख्यांक 5 के सामने, 'श्री एस० मिश्रा' के स्थान पर 'श्री एस० मित्र' सभ्य रहे जायेंगे ।

[बी०-20012/7/78-भ०नि० II]

ए० के० भट्टारai, अवर सचिव

#### CORRIGENDUM

S.O. 1451.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, No. S.O. 292, dated the 9th January, 1984, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th January, 1984, against serial number 5 for "Shri S. Mishra" read "Shri S. Mitra."

[V-20012/7/78-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

